Title Code: DELHIN28985.
DCP Licensing Number:
F.2 (P-2) Press/2023



आज का सुविचार

सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है।

🕦 क्राइम ब्रांच के घेरे में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सीएम के घर पहुंची एक टीम

116 विपक्षी गठबंधन में दरारें

🔐 लकपति दीदी कहाँ हैं? कोंग्रेस नेता पंचानन कानूनगो

क्या दिल्ली परिवहन विभाग के लिए महिला सुरक्षा से अधिक जरूरी है राजनीतिक दल के लिए वोट बैंक बनवाना

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा आज तक पैनिक बटन कंट्रोल सेंटर ही नहीं बनाया और साथ ही दिल्ली में चलने वाले 1 लाख आटो में 2020 से ही जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम की अनिवार्यता समाप्त कर रखी थी....

दिल्ली में सार्वजनिक सवारी सेवा
में कार्यरत सभी वाहनों में
जीपीएस/वीएलटीडी (पैनिक
बटन) लगाना अनिवार्य करने के
दिशा निर्देश जारी किए थे...

संजय बाटला

नर्ड दिल्ली। दिल्ली में निर्भया जैसी दुर्घटना दुबारा ना हो इसके लिए गह मंत्री सचिव के नेतृत्व में किमटी गठित हुई थी और साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय में उषा मेहरा की बेंच ने दिल्ली में सार्वजनिक सवारी सेवा में कार्यरत सभी वाहनों में जीपीएस/वीएलटीडी (पैनिक बटन) लगाना अनिवार्य करने के दिशा निर्देश जारी किए थे पर दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा आज तक पैनिक बटन कंट्रोल सेंटर ही नहीं बनाया और साथ ही दिल्ली में चलने वाले 1 लाख आटो में 2020 से ही जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम की अनिवार्यता समाप्त कर रखी थी पर पिछले महीने उसे शुरू करने के आदेश दिए थे पर अगले ही दिन आटो यूनियन के नेताओं के दबाव में आकर फिर से महिला सुरक्षा को दरकिनार कर इसको पुनः लागू करने के आदेश के बाद भी लाग नहीं किया। क्या दिल्ली परिवहन विभाग के लिए दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा से अधिक राजनीतिक वोट बैंक की कीमत ज्यादा है, बड़ा सवाल?



दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली की महिलाओं को जो फ्री की सुविधा प्राप्त वह सभी सुविधाएं किन्नरों को भी कराई जाए तत्काल मुहैया

दिल्ली किन्नर समाज की तरफ से सरकार से पुरजोर तरीके से अपील की गई है कि दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को जो फ्री सुविधाएं उपलब्ध की जा रही है वह सभी सुविधाएं किन्नरों को भी प्रदान की जाए। इसके लिए किन्नर समाज द्वारा उच्च न्यायालय दिल्ली में रिट दायर कर इन सभी सुविधाओं को किन्नर समाज के लोगों को प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार को आदेश पारित करने की मांग रखी है। अब देखना होगा की दिल्ली सरकार अपने आप सभी सुविधाए किन्नर समाज के लिए घोषित करेगा या कोर्ट के आदेश के बाद प्रदान करेगी।



सड़क परिवहन मंत्रालय ने 13,813 किमी राजमार्ग बनाने का रखा लक्ष्य



परिवहन विशेष न्यूज

चालू वित्त वर्ष में 13813 किलोमीटर राजमार्ग बनाने की तैयारी के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए रिकॉर्ड बनाना चाहता है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019–20 में 10237 किमी 2020–21 में 13327 किमी 2021–22 में 10457 किमी 2022–23 में 10331 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का लक्ष्य 2027– 28 तक दो लेन से कम राष्ट्रीय राजमार्गों को खत्म करना है।

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में 13,813 किलोमीटर राजमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है। अगर वह ऐसा करने में कामयाब रहता है तो यह एक रिकार्ड होगा।

मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019-20 में 10,237 किमी, 2020-21 में 13,327 किमी, 2021-22 में 10,457 किमी, 2022-23 में 10,331 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया। 2023-24 में दिसंबर तक 6,216 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा चुका था जबकि एक साल पहले की

समान अवधि में यह आंकड़ा 5,774 किलोमीटर था।

ये हैं मंत्रालय का लक्ष्य

सचिव अनुराग जैन ने कहा कि मंत्रालय का लक्ष्य 2027-28 तक दो लेन से कम राष्ट्रीय राजमार्गों को खत्म करना है। मार्च, 2012 में दो लेन से कम के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 25,517 किमी थी (जो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई का 30.1 प्रतिशत थी)।

वर्तमान में दो-लेन से कम राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की कुल लंबाई 14,350 किमी (कुल एनएच लंबाई का 9.8 प्रतिशत) है। जैन ने कहा कि सड़क मंत्रालय का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में संपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपये जुटाएगा।

1. Web Portal https://www.newsparivahan.com/ 2. facebook https://www.facebook.com/newsparivahan. 4. Linkedin https://www.linkedin.com/in/news-parivahan/ 6. Youtube https://www.youtube.com/@NewsParivahan पर आप सभी के लिए 24 घण्टे उपलब्ध 3. प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, A-4 पश्चिम विहार, नई दिल्ली: 110063 सम्पर्क: 9212122095, 9811732095 www.newsparivahan.com, www.newsparivahan Info@newsparivahan.com, myw.newsparivahan

सड़क हादसे बढ़े, लेकिन सुरक्षा के लिए घटा आवंटन

परिवहन विशेष न्यू

कंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए गुरुवार को जो अंतरिम बजट लोकसभा में पेश किया उसमें सड़क सुरक्षा के लिए महज 272 करोड़ रुपये ही निर्धारित किए गए हैं। पिछली बार यह राशि 330 करोड़ थी जिसे संशोधित कर 256 करोड़ कर दिया गया था। जबकि विशेषज्ञों के साथ ही संसद की स्थायी समिति भी सड़क सुरक्षा और शोध आदि के लिए आवंटन न बढ़ने पर चिंता जता चुकी है।

नई दिल्ली। मार्ग दुर्घटनाओं में 2022 में रिकार्ड वृद्धि के बावजूद सड़क सुरक्षा के लिए आवंटन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो सकी। केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए गुरुवार को जो अंतरिम बजट लोकसभा में पेश किया, उसमें सड़क सुरक्षा के लिए महज 272 करोड़ रुपये ही निर्धारित किए गए हैं। पिछली बार यह राशि 330 करोड़ थी,

पिछली बार यह राशि 330 करोड़ थी, जिसे संशोधित कर 256 करोड़ कर दिया गया था। इसमें शोध और सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड का धन भी शामिल है। अगर इसी प्रयोजन के लिए कुछ अन्य योजनाओं को भी जोड़ लिया जाए तो सड़क सुरक्षा के लिए निर्धारित धनराशि पांच सौ करोड़ भी नहीं है।

नईदुर्घटना बीमा योजना की

योजना

यह स्थिति तब जब विशेषज्ञों के साथ ही संसद की स्थायी समिति भी सड़क सुरक्षा और शोध आदि के लिए आवंटन न बढ़ने पर चिंता जता चुकी है। केंद्र सरकार नई दुर्घटना बीमा योजना लाने जा रही है। अभी इस योजना का ब्योरा नहीं दिया गया है, लेकिन संभावना है कि इसके तहत सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों को डेढ़ लाख रुपये तक की मदद दी जा सकती



है। बजट में फिलहाल इसके लिए आवंटन नहीं हुआ है।

^{नहा हुआ ह ।} हर साल बढ़ती है दुर्घटनाओं की मंख्या

देश में सड़क दुर्घटनाओं और उसमें जान गंवाने वालों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कुल 1.68 लाख लोगों ने हादसों में अपनी जान गंवाई। सरकार ने माना है कि दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधा

उपलब्ध करा बड़ी संख्या में लोगों को

बचाया जा सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार दुर्घटना बीमा योजना लाने की तैयारी में है। पिछले दिनों परिवहन सचिव अनुराग जैन ने कहा था कि फरवरी में इस योजना का एलान किया जा सकता है।

सड़क पर बस खड़ी करना पड़ा महंगा, युवकों ने डीटीसी के परिचालक को जमकर पीटा

परिवहन विशेष न्यूज

पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर बस टर्मिनल पर सड़क पर बस के खड़ा करने से नाराज स्कूटी सवार दो युवकों ने अपने साथियों के साथ मिलकर डीटीसी बस के परिचालक को पीट दिया। परिचालक को अपनी जान बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। मारपीट के दौरान आरोपितों ने पीडित से उसका बैग भी झपट लिया। जिसमें बस के टिकट व किराये के रुपये रखे हुए थे।

पूर्वी दिल्ली।बाबरपुर बस टर्मिनल पर सड़क पर बस के खड़ा करने से नाराज स्कृटी सवार दो युवकों



ने अपने साथियों के साथ मिलकर बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी डीटीसी बस के परिचालक को पीट पड़ी। दिया। परिचालक को अपनी जान मारपीट के दौरान आरोपितों ने

ग्राने के लिए काफी मशक्कत करनी पीड़ित से उसका बैग भी झपट लिया। जे। जिसमें बस के टिकट व किराये के मारपीट के दौरान आरोपितों ने रुपये रखे हुए थे। पुलिस ने घायल निसर को जग प्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती करवाया। उसकी शिकायत पर पुलिस ने मारपीट समेत कई धाराओं में प्राथमिकी की है।

निसर अपने परिवार के साथ सोनिया विहार में रहता है। वह डीटीसी बस में परिचालक है। उसकी ड्यूटी हिर नगर डिपो में है। वह बस चालक लित के साथ बाबरपुर बस टिर्मनल पहुंचा। सड़क किनारे दोनों बस को खड़ा करके खाना खा रहे थे। तभी एक स्कूटी पर दो युवक पहुंचे और बस को सड़क पर खड़ा देखकर गाली गलौज करने गले।

गाली-गलौज का विरोध करने पर पिटाई

शोर सुनकर परिचालक निसर बस से बाहर आ गया और गाली गलौज का विरोध किया। इतना सुनते ही दोनों आरोपित उसपर टूट पड़े। फोन करके अपने कुछ साथियों को बुला लिया। सभी ने मिलकर परिचालक को लात घूंसों से पीट दिया। आरोपितों की तलाश के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

दिंग्ट्सर्धीफलिबरलाइनेशनएंड वेद्यफेयरएवाइडद्रस्ट(पंजीकृत)

TOLWA

TOLWA
TOLWA

website: www.tolwa.in Email: tolwadelhi@gmail.com bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02–03–2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम –डीएल – 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25–01–2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय:– ३, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए –४ पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली ११००६३ कॉरपोरेट कार्यालय:– ५२९, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली ११००४२



गृहणियों में बढ़ रहा है मेंटल स्ट्रेस, एक्सपर्ट्स ने बताया खुश रहने का तरीका

बाहर जा कर काम करने वाली महिलाओं के पास फिर भी बाहर जाकर अपनी बात कहने का या मूड बदलने का एक ऑप्शन होता है, लेकिन हाउसवाइफ के साथ ऐसा नहीं है. ऐसे में वो घर में ही गुस्से में. द्वंद्व में, झुंझलाहट में या चिंता में पड़ी रहती हैं.

परे घर को संभालने वाली (गहणी/हाउसवाइफ) हमारी मां या पत्नी घर के हर एक सदस्य की जरूरत का ख्याल रखती हैं. उनका पुरा दिन घर की चार दीवारी में ही शुरू होता है और उसी में खत्म हो जाता है. सुबह से रात तक उनकी यही कोशिश रहती है कि किसी भी सदस्य को घर में कई तकलीफ न हो. ये सब वो किसके लिए करतीं हैं? अपने परिवार के लिए, परिवार की खशियों के लिए. फिर जब कभी वो जरा गुस्सा हो जाती हैं, तो हम उन्हें गलत समझने लगते हैं. लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो भी कितनी तरह के तनाव से जुझ रही है ? उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में कभी बात की है? ओनली माई हेल्थ की न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, बाहर जा कर काम करने वाली महिलाओं के पास फिर भी बाहर जाकर अपनी बात कहने का या मड बदलने का एक ऑप्शन होता है, लेकिन हाउसवाइफ के साथ ऐसा नहीं है. ऐसे में वो घर में ही गुस्से में द्वंद्व में, झुंझलाहट में या चिंता में पड़ी रहती हैं. इस रिपोर्ट में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट (Clinical Psychologist) ভাঁ. স্না मिलका (Dr. Pragya Malika) का कहना है कि हाउसवाइफ में तनाव कई वजहों से होता है, ऐसी स्थिति में वे अकेले रहने लग जाती हैं. परिवार में जब कॉर्नफ्लक्टस (झगडे और विवाद) बढते हैं तो वे एडजस्टमेंट की ओर जाते हैं. जब ये मुद्दे हल नहीं हो पाते तो सुसाइड, तलाक या अन्य मेंटल डिसऑर्डर (Mental Disorder) में बदल जाते हैं. इसे ही दुष्चक्र या विशियस साइकल (Vicious Cycle) कहते हैं.

को अपनाकर खुश रह सकती हैं. अपनी हॉबीज को करें याद

डॉ प्रज्ञा का कहना है कि अक्सर महिलाएं घर के काम में उलझकर अपनी हॉबीज (शौक) को भूल जाती हैं. जब ये निराशा या कुंठा बढ़ने लग जाए, तो अपने हुनर को याद करें. वो काम जिसे आप पूरे मजे के साथ करते थे, वो दोबारा करें. खुद सोचें कि आपको क्या करने में अच्छा लगता है. ऐसा करने से आत्मविश्वास बढेगा.

डॉ. प्रज्ञा के मुताबिक हाउसवाइफ इन तरीकों

परेशानी का कारण ढूंढे

डॉ. प्रज्ञा के मुताबिक हाउसवाइफ को ये देखना पड़ेगा कि उन्हें परेशानी किस बात से हो रही है. जब परेशानी की वजह मालूम हो जाए, तब उस पर काम करें. उस परेशानी को मैनेज करें. दरअसल, महिलाओं की टेंशन की एक वजह ये भी है कि महिला और पुरुष का दिमाग थोड़ा अलग तरह से काम करता है. जैसे महिलाएं इमोशनल होकर सोचती हैं और पुरुष लॉजिस्टिक तरीके से सोचते हैं.

नएदोस्तबनाएं

हाउसवाइफ अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए नए दोस्त बना सकती हैं. अपने घर के आसपास, रिश्तेदारों में या स्कूल-कॉलेज के दोस्तों के संपर्क में रहें और उनसे बात करते रहना भी कई बार इस स्ट्रेस से निकलने में मदद करता है.

अपने लिए टाइम निकालें

एक हाउसवाइफ होने के नाते आप क्या चाहती हैं? हाउसवाइफ होने के नाते आपके कुछ सपने होते हैं. तो यहां उन्हें सोचने की जरूरत है कि आप क्या चाहती हैं. खुद को खुश रखने के लिए अपना मी टाइम निकालें.

कुछ चीजों को हालात पर छोड़ दें

डॉ. प्रज्ञा का कहना है कि जिस सिचुएशन में आप कुछ कर नहीं सकतीं. जो हालात आपके बस से बाहर हैं, तो उन पर न सोचें.

आजादी और आध्यात्मिकता से जीवन हुआ आसान

महिलाओं में बढ़ा 'हैप्पीनेस लेवल'

स्टडी में सामने आया कि कम उम्र की युवतियां अपनी लाइफ से ज्यादा संतुष्ट हैं.

अब महिलाओं को मामूली बातों, जैसे क्या पहननां है क्या खाना है, कैसे बैठना या उठना है, इसके लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है. आजादी महिलाओं को खुशी दे रही है.

www.newsparivahan.com

क ताजा सर्वे में पता चला है कि कुछ दशक पहले की महिलाओं की तुलना में आज की युवतियां ज्यादा ख़ुश रहने लगी हैं और ये बदलाव उनमें अपनी लाइफ से जुड़ा हर फैसला लेने की उनकी बड़ी हुई क्षमता की वजह से है. दैनिक भास्कर अखबार में छपी न्यूज रिपोर्ट के अनुसार अब उन्हें मामूली बातों, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे बैठना या उठना है, इसके लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है. वो अपने फैसले खुद ले सकती है. इसमें आध्यात्मिकता भी एक वजह है जो महिलाओं के 'लेवल ऑफ हैप्पीनेस (Level of Happiness)' को

इस रिपोर्ट के अनुसार, पुणे के रिसर्च सेंटर 'दुष्टि स्त्री अध्ययन प्रोबधन केंद्र (DSAPK)' ने देश के 29 राज्यों की 43 हजार से ज्यादा महिलाओं से उनकी ख़ुशी को लेकर सवाल किए. इन महिलाओं की उम्र 18 साल से लेकर 70 साल के बीच की थी.



सर्वे में क्या निकला?

सर्वे में महिलाओं के साथ बातचीत में सामने आया कि कम उम्र की यवतियां अपनी लाइफ से ज्यादा संतुष्ट हैं. 18 से 40 साल के बीच की कम से कम 80 प्रतिशत प्रतिभागियों ने खुद को खुश बताया. इनमें से ज्यादातर महिलाएं आध्यात्म से भी जुड़ी हुई थीं, यानी पूजा-पाठ या किसी तरह का मेडिटेशन जैसी एक्टिवटी से वो जड़ी हुई थीं.

आजादी महिलाओं को खुशी दे रही

आपको बता दें कि भारत के अलावा दूसरे देशों में भी महिलाओं में हैप्पीनेस के लेवल को समझने के लिए स्टडी हुई है. यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया द्वारा की गई ऐसी ही एक स्टडी के लिए डे रिकंस्ट्रक्शन मेथड (Day

Reconstruction Method) की मदद ली गई, जिससे ये समझने की कोशिश थी कि एक दिन में महिलाओं के इमोशंस में कितना उतार-चढाव आता है. इसके नतीजों के अनुसार आजादी महिलाओं को ख़ुशी दे रही है.

परुषों के मकाबले बेटर हैंडलर

इस स्टडी में ये भी पाया गया कि फिट रहना भी महिलाओं को ज्यादा खश रखता है. अध्ययन के मृताबिक एक्सरसाइज करना महिलाओं को उनकी सैलरी मिलने जैसी ख़ुशी देता है. सर्वे में एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई कि अगर महिला और पुरुष को एक जैसी परेशानी दी गई, तो महिला उसे ज्यादा आसानी से डील

महिलाओं को हो सकती है दिल की बीमारी

कार्डियो वेस्कुकर डिजीज यानी सीवीडी की रोकथाम के बारे में महिलाओं जागरूकता की कमी है. खानपान और लाइफस्टाइल सही नहीं होने से महिलाओं में इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है . औरतें जिस तनाव का अनुभव करती हैं, अक्सर उनपर आसपास के लोगों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है.

दिल की बीमारी के लक्षण महिलाओं (Women) में उतने स्पष्ट रूप से नहीं नजर आते हैं, जितने पुरुषों में आते हैं. इसका मतलब यह है कि अगर पुरुषों में को दिल की समस्या होती है, तो एनजाइना जैसे विशिष्ट लक्षण दिख सकते हैं. जिन्हें आसानी से देखा जा सकता है और सही इलाज और देखभाल शुरू हो सकती है. वहीं महिला में यह समस्या होती है कोई लक्षण नहीं हो दिखते हैं. फिर जब तक बीमारी (Illness) का पता चलता है, ये इतनी गंभीर हो जाती है कि हर तीन में से एक महिला की मौत हृदय रोग के कारण हो जाती है.

जागरूकता की कमी

कार्डियो वेस्ककर डिजीज यानी सीवीडी की रोकथाम के बारे में महिलाओं जागरूकता की कमी है. खानपान और लाइफस्टाइल सही नहीं होने से महिलाओं में इस बीमारी का खतरा बढ जाता है. औरतें



नियमित जांच

महिलाओं में हृदय स्वास्थ्य लिए नियमित रूप से जांच जरूर करानी चाहिए. कोई लक्षण स्पष्ट रूप से

उनको हार्ट को लेकर सजग रहना चाहिए.

अगर सही समय पर बीमारी का पता चलता है तो महिलाओं में सीवीडी की बेहतर रोकथाम हो सकती

इन बातों का रखें ध्यान

जब हार्ट से जुड़ी बीमारी के बारे में पता करना मुश्किल हो, तो ऐसे में अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को सही रखें महिलाएं अपने खाने में हृदय को स्वस्थ रखने वाली चीजों को शामिल करें जैसे फल सब्जियां, और जिन चीजों में फाइबर ज्यादा हो. उन्हें जरूर अपने आहार में शामिल करें तनाव से दर रहें.

साफ सफाई से सुधर सकती है महिलाओं की मानसिक सेहतः रिसर्च

शोध में पाया गया है कि सफाई (Cleanliness) आपके मानसिक स्वास्थ्य पर कई सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. अलमारियों पर जमी धूल, किचन को पोंछना या कमरे को व्यवस्थित करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुए हैं. ये काम मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही फायदेमंद है, जितना मेडिटेशन या योग है. तो अगली बार जब तनाव हो तो घर की सफाई करने से मत कतराइयेगा



तनाव से निपटने के कुछ लोग योग, माइंडफुलनेस या यहां तक कि स्पा में मालिश लेते हैं ताकि तनाव कम हो. वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जो अलमारियों पर जमी धूल, किचन को पोंछना या कमरे को व्यवस्थित करते हैं. ये काम उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही फायदेमंद है, जितना लोगों के लिए मेडिटेशन या योग है. तो अगली बार जब तनाव हो तो घर की सफाई करने से मत कतराइयेगा . कुछ लोगों को साफ-सुथरा और व्यवस्थित घर तनावमुक्त करने में मद्द करता है. सफाई आपके मानसिक स्वास्थ्य कैसे असर करते है आइये जानते हैं.

अव्यवस्था अवसाद में योगदान कर सकती है

"व्यक्तित्व और सामाजिक मनोविज्ञान बुलेटिन" में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि जिन महिलाओं ने अपने रहने की जगह को अव्यवस्थित रखा, उनमें तनाव अधिक पाया गया. शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि जिन महिलाओं का घर अस्त-व्यस्त रहता है, उनमें कोर्टिसोल का स्तर अधिक होता है. वहीं व्यवस्थित महिलाओं में तनाव कम मिला इसलिए जरूरी है की घर को व्यवस्थित करना शुरू कर दें।

सफाई और सेहत

शोध में पाया गया है कि सफाई आपके मानसिक स्वास्थ्य पर कई सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. यह मूड में सुधार के साथ-साथ उपलब्धि और संतुष्टि की भावना प्रदान करने के लिए भी है.ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से सफाई आपको तनावमुक्त करने में मदद कर सकती है. तो अपने घर या ऑफिस की डेस्क को साफ करके देखिये तनाव छू मंतर होगा. इसके साथ ही थोड़ी शारीरिक मेहनत भी हो जाएगी जो आपको फिट रखने में मदद करेगी.

इस बात का रखें ध्यान

सफाई करना अच्छी बात है मगर ये हद से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. कई बार लोग सफाई में इतने ज्यादा आदी हो जातें हैं की दूसरों के घरों में भी डिस्टिंग करने लगते हैं. ऐसी अवस्था से बचें

अपनी बेटियों को करें प्रोत्साहित आत्मविश्वास भरना बेहद आवश्यक

के लिए बेहद ख़ास होती हैं।जितनी वो खास होती हैं उतनी ही ख़ास उनकी देखभाल भी होती है। जैसे-जैसे बेटियां बड़ी होती जाती हैं, वैसे-वैसे उनके प्रति माता-पिता की जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है।बात अगर पुराने जमाने की करें तो पहले घर-परिवार में बेटियों के पैदा होने पर उन्हें शगुन और साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता था। लेकिन आज के समय में भी बेटियां अपने आत्मविश्वास से ऊंचे से ं ऊंचा आसमान छूने की प्रतिभा रखती हैं। आज के समय में उनका दर्जा लड़कों से कम नहीं है। ये सब कुछ उनके माता-पिता की परवरिश का नतीजा होता है, जिससे उनका सिर गर्व से ऊपर उठता है। बहुत से माता-पिता होते हैं जो अपने बच्चों की तरक्की देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी हर दिशा में आगे बढ़े, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। यदि आप के घर में भी बेटी है तो आज का ये लेख खास आपके

लिए है, जिसके जरिये हम आपको बताएंगे

कि कैसे आप उसकी सही तरीके से

परवरिश करें जिससे वो आत्मविश्वास से

भरी रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं।

1. बेटी को करें प्रोत्साहित-जब बेटी बड़ी होती है, तो उसकी जरूरतें भी अल्फ होती चली जाती हैं। आप उसे जमीन से जुड़े रहना सिखाएं। अगर वो आगे बढ़ाने के लिए अपने भविष्य को लेकर कुछ चुनाव करती है तो उसे हताश ना करें। उसका साथ दें। एक बच्चे के लिए उसके माता-पिता का साथ बेहद जरूरी होता है। आप उसे प्रोत्साहित करें। ताकि उसके अंदर का आत्मविश्वास कम ना हो।

2. बेटी की करें तारीफ- आप अपनी बेटी को बताएं की वो दुनिया की सबसे खुबसूरत लड़की है। उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। उकसे अंदर ऐसी बात है जो उसे बाकियों से जुदा बनाती है। इससे बिटिया का आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा।

3. सीखने का दें अवसर-अगर बेटी को संगीत या किसी भी तरह की एक्टिविटी में इन्ट्रेस्ट हैं लेकिन वो इन में फिट नहीं बैठते। ऐसे में अगर आप उसका साथ नहीं

देंगे तो उसका मनोबल टूटता चला जाएगा। उसे सीखने का अवसर जरुर दें। उसे अपनी असल प्रतिभा धीरे-धीरे खुद समझ आएगी और वो आगे बढ़ेगी।

बेटी को सिखाएं समाजिकता-बेटी को समाज और उससे जुड़ी बातों के बारे में सिखाएं। उसे सिखाएं कि अगर उससे कोई दोस्ती नहीं करता तो उसका क्या कारण हो सकता है। समाज के प्रति उसके अंदर नकारात्मकता ना भरें। वरना एक समय के बाद वो समाज को नकारात्मक नजरिये से देखने लगेगी। उसे सभी पहलुओं के बारे में जरुर सिखाएं।

5. बढाएं बेटी की क्षमता-अगर आपकी बेटी अपना होमवर्क कर रही है तो यूं ही उसकी मदद ना करें। वो जब तक आपसे मदद नहीं मांगती तब तक उसकी मदद मत करें। उसे उसकी क्षमता के अनुसार काम करने दें। उसे अपने दम में हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही प्रोत्साहित करें।

6.ना थोपें अपनी मर्जी- आज के



समय में बेटियां स्पोर्ट्स को ज्यादा पसंद कर बनाएं। उसकी खुबियों को प्रोत्साहित करने रही हैं, और उसी में अपना भविष्य भी तय कर रही हैं। अगर वो एक जिमनास्टिक बनना चाहती है या फुटबॉल खेलना चाहती है तो उसे आगे बढ़ने दें, ना की अपना फैसला या अपनी चाह उसपर थोपें। आप ये जरुर पता लगा सकते हैं, कि वो किस खेल को खेलने के लिए ज्यादा सक्षम है। आप

7. मत बनाइए कमजोर-आप आप एक बेटी के माता-पिता हैं तो ये बिलकुल भी ना सोचें कि वो एक बेटी होने के नाते जीवनभर संघर्ष करेगी। आप उसकी किसी ताकत या कमजोरी की धारणा बिलकुल ना

खुद उसके लिए कोई खेल तय ना करें।

के साथ उसकी कमजोरियों को भी समय पर पहचानें और उसे सुधारने की कोशिश

8. सेक्सिज्म के लिए करें तैयार-बहुत लोगों की सोच है कि बेटियां वो काम नहीं कर सकती जो बेटे कर सकते हैं। अगर आप अपनी बेटी को वो टीवी शो या फ़ल्मिं देखते हुए नोटिस करते हैं जो पूरी गर्ल्स पर आधारित होती है तो उसे समझिये और उसे सेक्सज्म के लिए तैयार करें।

9. बेटी को दिखाएं रोल मॉडल-अक्सर ऐसा होता है जब भी आप कोई न्युज

आप आप एक बेटी के माता-पिता हैं तो ये बिलकुल भी ना सोचें कि वो एक बेटी होने के नाते जीवनभर संघर्ष करेगी। आप उसकी किसी ताकत या कमजोरी की धारणा बिलकुल ना बनाएं। उसकी खुबियों को प्रोत्साहित करने के साथ उसकी कमजोरियों को भी समय पर पहचानें और उसे सुधारने की कोशिश करें।

देखते या पढ़ते हैं तो उसमें आपको कई महिलाएं सीनेटरी, खिलाड़ी, चिकित्सक या एथलीट दिखेंगी। ये अच्छा तरीका होता है अपनी बेटी को इन महिलाओं के बारे में दिखाना और समझाना। आप इम्नें से कोई भी अपनी बेटी के लिए रोल मॉडल चुनने में उसकी मदद कर सकते हैं।

तो ये कुछ ऐसी खास टिप्स हैं, जिनकी मदद से आप अपनी बिटिया को अच्छी परवरिश देने के साथ उसमें आत्मविश्वास भर सकते हैं। अगर आपकी भी बेटी है तो आप हमारी बताई हुई टिप्स को जरुर आजमाएं। आपको इससे बेहतर परिणाम मिलेगा।

'हमें तो मौका ही नहीं मिला,

कोर्ट का जल्दबाजी में आया फैसला', ज्ञानवापी को लेकर

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के

अध्यक्ष का बयान

प्रदर्शन में बोले केजरीवाल- 'गली-गली में शोर है, भाजपा वोट...', धारा १४४ के तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सैकड़ों कार्यकर्ता हिरासत में

परिवहन विशेष न्यूज

चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के चुनाव परिणाम के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। हालांकि इससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए जगह-जगह बैरिकेडिंग लगा दी है। इसके साथ ही प्रदर्शन में शामिल होने पंजाब और हरियाणा से आ रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सिंघु बॉर्डर पर रोक लिया और 25 को हिरासत में ले लिया है।

नईदिल्ली।AAP Protest For Chandigarh Mayor Election: आम आदमी पार्टी चंडीगढ मेयर इलेक्शन के चनाव परिणाम के खिलाफ आज दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। हालांकि इससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन को रोकने के लिए जगह-जगह बैरिकेडिंग लगा दी है।

इसके साथ ही प्रदर्शन में शामिल होने पंजाब और हरियाणा से आ रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सिंघु व टीकरी बॉर्डर पर रोक लिया। इसके खिलाफ आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल से लेकर आतिशी सौरभ भारद्वाज व तमाम नेता अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। यहां पढें दिनभर की अपडेटस...

बीजेपी कार्यकर्ता लिए गए हिरासत में

सीएम अरविंद केजरीवाल के ईडी पूछताछ में शामिल न होने को लेकर बीजेपी ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। इसमें शामिल हजारों बीजेपी कार्यकर्ता जब आम आदमी पार्टी कार्यालय की ओर बढ़े तो बड़ी संख्या में तैनात पुलिस बल द्वारा बैरिकेड्स पर रोकने का प्रयास किया। कार्यकर्ता बैरिकेड्स तोड़ कर आम आदमी पार्टी कार्यालय की और दौड़े तो उन्हें पुलिस ने बल प्रयोग कर रोक लिया और हिरासत में लेकर इन्द्रप्रस्थ स्टेट थाने ले

बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़े केजरीवाल और भगवंत मान



सीएम केजरीवाल और भगवंत मान कार्यकर्ताओं को संबोधित कर बीजेपी पार्टी मख्यालय की तरफ निकल गए। इस दौरान पलिस की भारी तैनाती की गई। पलिस ने कहा कि आप का प्रदर्शन गैरकानूनी है, तुरंत बंद कर दें। सड़क

बीजेपीकेपापका घड़ा भर गया है

को खाली कर दें।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद के जरीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ₹अक्सर आरोप लगते थे कि भाजपा चुनाव गड़बड़ करके जीतती है। हम सुना करते थे कि भाजपा फर्जी वोट पड़वाती है लेकिन कभी सबूत नहीं मिला। चंडीगढ़ का चुनाव दिखाता है कि इनके(भाजपा) पाप का घडा भर गया था। जब

पाप का घड़ा भर जाता है तो प्रकृति अपनी झाड़

केजरीवाल और भगवंत मान पहुंचे आप

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आप दफ्तर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। केजरीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने वोटों की चोरी की। अगर पीएम नरेंद्र मोदी 2024 में चनाव जीत गए तो इनका नाम नरेंद्र पतिन हो जाएगा। वहीं भगवंत मान ने कहा कि अगर गड़बड़ी ही करनी है तो चुनाव क्यों करते हो, तानाशाही शुरू कर दो।

विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी मेयर

'देश जानता है भाजपा ने की धोखाधडी'

आप नेता और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर आरोप लगाया कि 'देश जानता है कि बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कैसे धोखाधड़ी की। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान आज बीजेपी कार्यालय पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस विरोध प्रदर्शन से पहले , हमारे विधायकों, पार्षदों और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर हिरासत में लिया जा रहा है। क्या बीजेपी अरविंद केजरीवाल से इतनी डरी हुई है कि वे यह

आने वाले कार्यकर्ताओं की संख्या काफी कम है। पुलिसकर्मियों का कहना है कि किसी को भी

पुलिसकर्मियों का कहना है कि सिर्फ उन लोगों को रोका जा रहा है जो गाडी पर या तो झंडा लगाकर आ रहे हैं या उन्होंने गाड़ी पर कोई बैनर

बढा दी गई है। जहां आप चंडीगढ मेयर चनाव में कथित धोखाधडी को लेकर भाजपा मख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी, वहीं भाजपा ने कहा है कि उसके सदस्य अरविंद केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन करेंगे।

विरोध प्रदर्शन नहीं होने दे रहे हैं?

टीकरी बॉर्डर पर भी रोके जा रहे कार्यकर्ता टीकरी बार्डर पर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। हालांकि यहां पर

रोका नहीं जा रहा है। ज्यादातर लोग बहादुरगढ़ से मेटो में सवार होकर दिल्ली पहुंच चके हैं। उन्हें कैसे रोका जाए।

लगाया हुआ है।

पहले वोट चोरी किए अब...

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक केजरीवाल का दावा है कि पूरी दिल्ली में बैरिकेडिंग कर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली आने से रोका जा रहा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हए लिखा. 'पहले चंडीगढ मेयर चुनाव में वोट चोरी किए। अब इसके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आ रही जनता को जगह-जगह दिल्लीभर में रोका जा रहा है।

ज्ञानवापी पर मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक शुक्रवार को हो रही है। यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जमीयत उलेमा ए हिंद के मुख्यालय में हो रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्ला रहमानी ने कहा कि ज्ञानवापी में जो

हुआ इससे मुस्लिमों के साथ अमन

प्रसंद लोगों को धक्का पहुंचा। वहीं

मौलाना अरशद मदनी ने भी अपनी

राय रखी।

नईदिल्ली।ज्ञानवापी पर मुस्लिम संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक शुक्रवार को हो रही है। यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा जमीयत उलेमा ए हिंद के मुख्यालय में हो रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्ला रहमानी ने कहा कि ज्ञानवापी में जो हुआ, इससे मुस्लिमों के साथ अमन पसंद लोगों को धक्का पहुंचा।

उन्होंने कहा कि यह इतिहास गढ़ा गया, कोर्ट ने जल्दबाजी में निर्णय दिया। दसरे को कहने का मौका। नहीं दिया। इससे इंसाफ पसंद लोगों के भरोसे पर चोट पहुंची है। बाबरी मस्जिद में भी कोर्ट ने माना कि मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं थी, लेकिन आस्था को देखकर एक पक्ष में फैसला कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी फैसले पर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राष्ट्रपति से भी मिलने को समय मांगेंगे।

फैसला देने में कोर्ट में लचीलापनः मदनी

वहीं दारुल उलूम देवबंद के वर्तमान प्राचार्य अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमान मुल्क की आजादी के बाद इस तरह की मसाइल में घिरा हुआ है। मथुरा, संभल. ज्ञानवापी और बाबरी जैसे मस्जिद के मामले उठते रहे, लेकिन अब जिस तरह से ये मसाइल उठे हैं; उससे महसूस होता है कि कानून के आलोक में न्याय देने वाले कोर्ट में लचक और ढील पैदा हुई है, जो इबादतगाहों पर कब्जे में सहलियत मिली है। उन्होंने कहा कि बाबरी ने जो रास्ता खोला कि धर्म आधारित मुकाबला होगा तो फैसला कानून आधार पर नहीं हो रहा। यह लोकल कोर्ट से लेकर सप्रीम कोर्ट तक है। इन तमाम कानूनी किताबों पर आग लगाओ। मुल्क इससे नहीं चलेगा । इसकी जद में जैन बौद्ध, ईसाई भी आएंगे ।

एकतरफा फैसले के बाद हम कहां जाएं:

महमूद मदनी ने कहा कि भारत की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर बड़ा सवालिया चिन्ह लग गया है । जिस तरह से एक तरफा तरीके से जाते जाते जज ने इस तर्क का फैसला दे दिया, फिर ऊपर की अदालतें तकनीकी कारणों से दखल देने को तैयार नहीं तो दूसरा पक्ष कहां रोएगा।ऐसी परिस्थिति है कि कुछ समझ नहीं आरहा है कि क्या करें क्या न करें। बात इस तलक न जाएं की खराबी तक चला जाए. बडे संघर्ष से आजादी मिली है।

टेंट हाउस के गोदाम में चोरी कर रहे युवक को पीट-पीटकर मार डाला

वह विनोद के साथ 27 जनवरी की रात को एक टेंट हाउस के गोदाम में चोरी करने के लिए गया था। वह चोरी कर ही रहे थे कि गोदाम के कर्मचारियों ने उन्हें पकड लिया वह तो किसी तरह से वहां से भाग निकला विनोद को उन्होंने छोड़ा नहीं। पुलिस ने टेंट हाउस पर छापेमारी कर आफताब को गिरफ्तार किया है।

पर्वी दिल्ली। ज्योति नगर इलाके में टेंट हाउस के गोदाम में चोरी करने गए युवक की पीटकर हत्या कर दी गई। उसके शव को उत्तर प्रदेश के मुरादनगर स्थित सुराना गांव में ठीकाने लगा दिया। हत्या के पांच दिन के बाद पलिस ने विनोद बहादुर के शव को गांव की झाड़ियों से बरामद कर लिया है।

अन्य आरोपियों की तलाश में पलिस पलिस ने टेंट हादस के कर्मचारी आफताब को

गिरफ्तार किया है । उसे रिमांड पर लेकर पलिस उसके साथियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने इस मामले में अगवा व हत्या की धारा में प्राथमिकी की है। विनोद बहादर परिवार के साथ हरदेव परी गली नंबर-4 में रहता था। परिवार में मां व अन्य सदस्य हैं। विनोद की मां सारा ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी कि 27 जनवरी की रात को उनके बेटे को आखिरी बार ईस्ट लोनी रोड स्थित जल बोर्ड के कार्यालय के पास देखा गया था।

टेंट हाउस गोदाम में चोरी करने गया था वह घर नहीं आया और उसका फोन भी बंद



है। पलिस ने उस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तो विनोद एक शख्स के साथ दिखाई दिया। पुलिस ने उसकी पहचान की और हिरासत में लेकर उससे पृछताछ की। उसने पुलिस को बताया कि वह विनोद के साथ 27 जनवरी की रात को एक टेंट हाउस के गोदाम में चोरी करने के लिए गया था। वह चोरी कर ही रहे थे कि गोदाम के कर्मचारियों ने उन्हें पकड़ लिया।

वह तो किसी तरह से वहां से भाग निकला, विनोद को उन्होंने छोड़ा नहीं। पलिस ने टेंट हाउस पर छापेमारी कर आफताब को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस उपायुक्त डॉ. जाय टिर्की ने बताया कि आरोपित ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसने विनोद को बंधक बनाकर जमकर पीटा था। पिटाई से उसकी मौत हो गई थ। पुलिस से बचने के चक्कर में उसने शव को मुरादनगर के गांव में

बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीएसआर के तहत किया सफदरजंग अस्पताल का सहयोग

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास

गोयल और डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल

को घर में नजरबंद रखा गया है। दिल्ली के मंत्री

गोपाल राय ने शुक्रवार को एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस

में कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित

धोखाधड़ी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के

खिलाफ आप के विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली

विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल और डिप्टी

मेयर आले मोहम्मद इकबाल को घर में नजरबंद

पार्टी दफ्तरों में मल्टीलेयर बैरिकेडिंग

पार्टी (आप) और भाजपा के प्रदर्शन के मद्देनजर

अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ सुरक्षा

मध्य दिल्ली में मल्टीलेयर बैरिकेडिंग और

पुलिस ने कहा कि शुक्रवार को आम आदमी

नर्इ दिल्ली। बैंक ऑफ बडौदा ने अपने सीएसआर फंड के तहत सफदरजंग अस्पताल को अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। यह सीएसआर प्रोग्राम सफदरजंग अस्पताल के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में मिल का पत्थर साबित होगा। बैंक ने स्वास्थ्य देखभाल पहुंच बढाने के प्रति समर्पण प्रदर्शित करते हुए उदारतापूर्वक इन्फ यूजन पंप, व्हीलचेयर, वॉकर, कमोड चेयर और बैसाखी जैसे उपकरणों की सहायता प्रदान की।

बैंक ऑफ बडौदा के महाप्रबंधक, राकेश शर्मा और उप महाप्रबंधक, श्री निशांत द्वारा

ये सहायता सफदरजंग अस्पताल

को उपलब्ध करवाई गई।

इन्फ्यूजन पंप रोगी की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जबिक गतिशीलत सहायता. व्हीलचेयर , वॉकर, कमोड कुर्सियां और बैसाखी रोगियों के मुख्य धारा में लाने का कार्य करेगी।

यह भव्य सहायता कार्यक्रम सफदरजंग अस्पताल की अधीक्षक डॉ. वंदना तलवार की उपस्थिति में हुआ, जिन्होंने बैंक के उदार समर्थन



के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि इस प्रकार की जिम्मेदारी को मजबती से पुरा करना बैंक की समुदाय के प्रति स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है।

इस मौके पर बैंक ऑफ़ बड़ोदा के जनरल मैनेजर राकेश शर्मा ने कहा कि ₹सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के मिशन में सफदरजंग अस्पताल के साथ साझेदारी करके हमें ख़ुशी हो रही है। यह पहल उन समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डीएस आर लक्ष्यों के अनुरूप है।

बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी कॉर्पोरेट जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित है और योगदान दे रहा है। यह पहल उन समदायों में स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच पर स्थायी और सार्थक प्रभाव

सफदरजंग अस्पताल में बैंक ऑफ बड़ौदा की नई निर्मित शाखा का रिबन काटने का समारोह अतिरिक्त एमएस डॉ. पीएस भाटिया. अतिरिक्त एमएस डॉ. जयंती मणि, डॉ. नीरज गुप्ता, सीएसआर टीम और श्री की उपस्थिति में प्रोफेसर डॉ. वंदना तलवार चिकित्सा अधीक्षक के नेतत्व में किया गया। रोहित चौधरी मुख्य महाप्रबंधक भी इस मौके पर मौजूद रहें।

बैंक ऑफ बड़ौदा एक अग्रणी सार्वजनिक बैंक है जो उत्कृष्टता और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। 108 वर्षों की समृद्ध विरासत के साथ, बैंक आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा रहा है।

सफदरजंग अस्पताल भारत का बहत ही प्रमख अस्पताल है प्रतिदिन हजारों लोग यहां अपना इलाज करवाने आते हैं। यह अस्पताल अपनी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए समर्पित है। रोगी देखभाल, अनुसंधान और शिक्षा पर ध्यान देने के साथ, अस्पताल स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सबसे आगे है।

पार्टी के 7 विधायकों के संपर्क में है और 25 करोड़ रूपये देने की बात भी कह रही है। यह आरोप केजरीवाल ने भाजपा पर लगाया था।

क्राइम ब्रांच के घेरे में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सीएम के घर पहुंची एक टीम; जानिए क्या है मामला

नई दिल्ली। शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। क्राइम ब्रांच की टीम आप विधायकों के खरीदने की कोशिश से जुड़े मामले में सीएम केजरीवाल के घर गई थी। हालांकि, अरविंद केजरीवाल के घर पर न मिलने से वापस लौट आई है।

आपने भाजपा पर लगाया था ये आरोप

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। भाजपा आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों के संपर्क में है और 25 करोड़ रुपये देने की बात भी कह रही है। यह आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर लगाया था।

भाजपा ने आरोपों पर मांगे साक्ष्य इसके बाद भाजपा ने दिल्ली पुलिस में इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में भाजपा के अन्य पदाधिकारी, सांसद व विधायक दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोडा से मिलकर लिखित शिकायत की। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ ही दिल्ली



सरकार की मंत्री आतिशी, विधायक दुर्गेश पाठक व दिलीप पांडे पर झुठ बोलने का आरोप लगाकर कानूनी कार्रवाई की मांग की

शनिवारको फिर जाएगी टीम

साथ ही भाजपा ने मुख्यमंत्री के आरोप को तथ्यहीन बताते हुए उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने की चुनौती दी थी। अब क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। पलिस ने बताया कि टीम सीएम से जांच में सहयोग के लिए गई थी। टीम यह जानना

चाहती है कि वे कौन लोग हैं, जो विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहे है, ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। आवास पर मुख्यमंत्री के नहीं मिलने पर पुलिस की टीम लौट आई। पुलिस ने बताया कि इस सम्बंध में

जानकारी देने के लिए शनिवार को फिर से पुलिस की टीम मुख्यमंत्री आवास पर जाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि पुलिस टीम आई थी, सीएम कार्यालय का स्टाफ नोटिस लेने के लिए तैयार था, मगर पुलिस बिना नोटिस दिए लौट गई।

भी कह रही है। यह आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर लगाएँ थे। ED की पूछताछ में केजरीवाल के शामिल नहीं होने पर बीजेपी ने CM पर बोला हमला, कहा- पापों का होगा हिसाब

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। भाजपा आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों के संपर्क में है और 25 करोड़ रुपये देने की बात

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी की जांच में शामिल न होने पर दिल्ली बीजेपी ने जांच से भागने का आरोप लगाया है। भाजपा की प्रदेश सचिव बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस को अवैध बता रहे हैं तो फिर उन्हें न्यायालय का रुख क्यों अभी तक नहीं किया है? वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने भी जमकर हमला बोला है।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद के जरीवाल द्वारा ईडी की जांच में शामिल न होने पर दिल्ली बीजेपी ने जांच से भागने का आरोप लगाया है। भाजपा की प्रदेश सचिव बांसुरी स्वराज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस को अवैध बता रहे हैं तो फिर उन्हें न्यायालय का रुख क्यों अभी तक नहीं किया है? उन्होंने कहा कि देश का कानुन एक सामान्य व्यक्ति और मुख्यमंत्री को समान अधिकार देता है, इसलिए यह अरविंद केजरीवाल के



अधिकार क्षेत्र में नहीं है तय करना समन अवैध है या गैर कानुनी है। इसके लिए अदालत में जाना चाहिए।

कई नेताओं को जमानत नहीं मिल रही: बांसुरी स्वराज ने कहा कि केजरीवाल को शोभा नहीं देता कि सीएम होने के बाद भी जांच से भागने का वह बार-बार प्रयास कर रहे हैं। शराब घोटाले में कोर्ट ने कहा है कि 90 से 100 करोड़ रुपये पिछले दरवाजे से वापस लिए हैं। इस देश की विभिन्न अदालत भ्रष्टाचार में लिप्त आप नेताओं को जमानत नहीं दे रही है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को अभी तक जमानत नहीं मिली है। पापों का होगा हिसाबः कपिल मिश्रा

वहीं, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल ईडी से भाग रहे हैं। वह कितना भी भागे उनके चोरी और पापों का हिसाब होगा। इसके इतर भाजपा ने आप कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के प्रदर्शन के होर्डिंग्स फाडने पर आप की बोखलाहट करार दिया है।



उपभोक्ता ने एक साल में तीन बार में सोढ़ीस सुपर मार्केट से सामान खरीदा था। हर उससे कैरी बैग के पैसे लिए गए। तीन बार में उससे 40 रुपये कैरी बैग के ले लिए गए। इस पर उसने कंपनी को लीगल नोटिस भेजा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने सोढ़ीस मार्केट को उपभोक्ता को 45 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।

गुरुग्राम। सेक्टर-55 सोढ़ीस सुपर मार्केट से सामान खरीदने के दौरान उपभोक्ता से कैरी बैग के लिए पैसे लेने पर उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता को 45 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य खुशविंद्र कौर ने दिया है।

दो कैरी बैग के लिए 20 रुपये उपभोक्ता ने एक साल में तीन बार में सोढ़ीस सुपर मार्केट से सामान खरीदा था। सेक्टर-56 निवासी समन्वय भुटानी निवासी अपनी शिकायत में बताया कि वह 16 अप्रैल 2021 को सेक्टर-55 स्थित सोढ़ीस सुपर मार्केट में सामान खरीदने के लिए गए थे। उन्होंने अपने घर के लिए 1730 रुपये का सामान खरीदा था। वहां पर उनसे दो कैरी बैग के लिए 20 रुपये लिए गए। इसके लिए उन्होंने 24 अप्रैल को एक लीगल नोटिस भी भेजा था। इसके बाद वह पांच नवंबर 2021 को सोढ़ीस मार्केट पर गए थे। वहां पर उन्होंने 469 रुपये का घर का सामान खरीदा था। उस बार सोढ़ीस मार्केट की तरफ से 10 रुपये लिए गए। उन्होंने इस बार भी कंपनी को लीगल नोटिस भेजा था।

www.newsparivahan.com

पैसे लेने पर भेजा कानूनी जेरिक

तीसरी बार वह 26 नवंबर 2021 को घर के लिए सामान खरीदने के लिए गए थे। उन्होंने 938 रुपये का सामान लिया था। उस बार भी उनसे कैरी बैग के लिए 10 रुपये लिए गए। मामले की सुनवाई के दौरान सोढ़ीस मार्केट की तरफ से दलील दी गई थी कि कैरी बैग वापस करने पर पैसे वापस कर दिए जाते है।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने सोढ़ीस मार्केट को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता से लिए कैरी बैग के लिए 40 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज की दर से वापस करें।शिकायतकर्ता को परेशान होने पर 45 हजार रुपये का मुआवजे के साथ ही 33 हजार रुपये कानूनी खर्च होने पर दिए जाएं।

दिल्ली में किसानों का फिर होगा जमावड़ा, आट फरवरी को ट्रैक्टर और पैदल मार्च कर जाएंगे किसान

परिवहन विशेष न्यूज

यदि किसी ने रोका तो चिल्ला बॉर्डर यानी नोएडा दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की कोई आवाजाही नहीं होने दी जाएगी। इस फैसले पर पंचों ने मुहर लगा दी है। पंचायत से पहले किसानों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उनकी बसों को गांव में ही रोका जा रहा है। सुखवीर खलीफा ने कहा कि हम व्यवस्था बनाने आए हैं।

नोएडा। अपनी मांगों को लेकर 53 दिन से धरने पर बैठे किसानों ने शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण के बाहर महापंचायत की। इसमें दादरी के 24 गांव और नोएडा प्राधिकरण के 81 गांव के किसान शामिल हुए। महापंचायत में फैसला लिया गया कि किसान 8 फरवरी को ट्रैक्टर और पैदल मार्च करते हुए दिल्ली जाएंगे और वहां धरना देंगे। सील बॉर्डर को सील करने का प्लान

एनटीपीसी के सीएमडी का घेराव भी करेंगे। यदि किसी ने रोका तो चिल्ला बॉर्डर यानी नोएडा दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की कोई आवाजाही नहीं होने दी जाएगी। इस फैसले पर पंचों ने मुहर लगा दी है। सुखवीर खलीफा ने कहा कि बहुत पीड़ा सहन कर ली है। अब आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करेंगे। ठोस कदम उठाया जाएगा। यहां से लेकर एनटीपीसी और ग्रेटर नोएडा तक पीड़ित हैं। यहां जो होगा स्पष्ट होगा। पंचायत से पहले किसानों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उनकी बसों को गांव में ही रोका जा रहा है। सुखवीर खलीफा ने कहा कि हम व्यवस्था बनाने आए हैं। आप इस तरह रोकेंगे तो गलत है। इसके बाद किसान और पुलिस प्रशासन ने आपस में बातचीत की और महापंचायत शुरू की गई। इस महापंचायत में सीटू और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के किसानों के अलावा सपा कार्यकर्ता भी मौजुद रहे।

यह है विवाद

नोएडा प्राधिकरण ने भू अर्जन अधिनयम 1984 में वर्णित प्रविधान के मुताबिक 16 गांव की 19 अधिसूचनाएं को एक किसान की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। इस चुनौती पर उच्च न्यायालय ने किसानों को 64.70 प्रतिशत की दर से मुआवजा और 10 प्रतिशत आबादी भूखंड देने का आदेश 21 अक्टूबर 2011 को दिया गया। इस आदेश में ऐसे किसान जिनकी याचिका खारिज कर दी गई या जो न्यायालय नहीं गए, उनका निर्णय प्राधिकरण को लेने का निर्देश दिया गया।

न्यायालय के आदेश के बाद प्राधिकरण ने 191वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया कि 10 प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड (जिन्हें पूर्व में 5 प्रतिशत विकसित आबादी भूखंड मिल चुका है उन्हें अतिरिक्त 5 प्रतिशत भूखंड) या इसके क्षेत्रफल के समतुल्य मुआवजा सिर्फ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा, जो उच्च न्यायालय के आदेश 21 अक्टूबर 2011 में शामिल हुए थे। प्राधिकरण ने माना कि ऐसे किसान जिन्होंने न्यायालय में अधिसूचना को चुनौती दी लेकिन उनकी याचिका को निरस्त कर दिया गया और ऐसे किसान जिन्होंने अधिसुचना को चुनौती ही नहीं दी, वे पात्र नहीं है।

किसानों की मांग और प्राधिकरण के तथ्य

किसानों की मांग है कि 1997 से 2014 के सभी किसान जो कोर्ट गए या नहीं सभी को 64.7 प्रतिशत की दर से मुआवजा और 10 प्रतिशत विकसित जमीन दी जाए। इस पर प्राधिकरण ने बताया कि न्यायालय के 21 अक्टूबर 2011 के आदेश के तहत 30 मार्च 2002 से 31 मार्च 2014 की अविध में के दौरान हस्ताक्षरित हुई भूमि के सापेक्ष 64.70 प्रतिशत की दर से मुआवजा दिया जा चका है।

नियमानुसार जो किसान कोर्ट गए सिर्फ उन्हीं को 10 प्रतिशत विकसित भूमि (5 प्रतिशत विकसित भूमि मिल चुकी है और 5 प्रतिशत दी जानी थी) के समतुल्य पैसा दिया जा चुका है। ऐसा करीब 900 करोड़ रुपये दिया गया। जो किसान न्यायालय नहीं गए, उन्होंने प्राधिकरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद भी धरना प्रदर्शन को देखते हुए उनकी मांगों को बोर्ड में रखते हुए शासन को भेजा गया। कई बार रिमाइंडर भी जारी किया गया।

1997 से लेकर 2014 तक सैकड़ों किसान हैं। यदि इनको भूमि के समतुल्य पैसा दिया गया तो ये करीब सात हजार करोड़ का अतिरिक्त भार होगा। लिहाजा इसमें शासन से ही निर्णय हो सकता है। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि आबादी विनियमावली 2011 के तहत नोएडा प्राधिकरण 5 प्रतिशत भूखंड के लिए 450 वर्गमीटर से ज्यादा का आवंटन नहीं कर सकता। नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तो हम दे सकते हैं, लेकिन संशोधन या कानून में बदलाव शासन स्तर पर हो सकता है। जिसमें समय लगता है।

अरावली की पहाड़ी से लेकर फरूखनगर तक... गुरुग्राम में कई एकड़ में बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

परिवहन विशेष न्यज

सोहना नगर परिषद की ओर से बीते दिनों 48 फार्म हाउस मालिकों को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद अरावली पहाड़ी की तलहटी से लगते दो दर्जन अवैध निर्माण फार्म हाउस और चारदीवारी को नगर परिषद ने जेसीबी मशीन से ढहा दिया। फरुखनगर के ताजनगर गांव में करीब साढ़े छह एकड़ में अवैध रूप से कट रही चार कालोनियों में तोडफोड अभियान चलाया गया।

गुरुग्राम। जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को गुरुग्राम के अलग-अलग हिस्सों में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। अरावली की पहाड़ी में गुरुवार से चल रहे तीन दिवसीय तोड़फोड़ अभियान के तहत दूसरे दिन परिषद ने तीन जेसीबी मशीन लगाकर दो दर्जन अवैध निर्माण जमींदोज कर

48 फार्म हाउस मालिकों को

परिषद की इस कार्रवाई से अरावली पहाड़ी में अवैध निर्माण करने वाले फार्म हाउस मालिकों में हड्कंप मच इसके अलावा फरुखनगर के एक कॉलोनी दो ए

फार्म हाउस मालिकों में हड़कंप मच गया। दूसरी ओर कोर्ट से स्टे होने के कारण करीब 20 अवैध फार्म हाउस मालिकों को फिलहाल तोड़फोड़ कार्रवाई से राहत मिल गई।

सोहना नगर परिषद की ओर से बीते दिनों 48 फार्म हाउस मालिकों को नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद अरावली पहाड़ी की तलहटी से लगते दो दर्जन अवैध निर्माण फार्म हाउस और चारदीवारी को नगर परिषद ने जेसीबी मशीन से ढहा दिया। इसके अलावा फरुखनगर के ताजनगर गांव में करीब साढ़े छह एकड़ में अवैध रूप से कट रही चार कालोनियों में तोड़फोड़ अभियान चलाया गया। डीटीपीई की तरफ से इस माह अब लगातार अवैध कालोनियों पर तोड़फोड़ अभियान चलाया जाएगा।

डीटीपी एन्फोर्समेंट मनीष यादव के नेतृत्व में चलाए गए तोड़फोड़ अभियान में चार स्ट्रक्चर, 15 डीपीसी और चारो कालोनी में करीब 800 मीटर रोड नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया। इसमें एक कॉलोनी दो एकड़, दूसरी एक एकड़, तीसरी कॉलोनी डेढ़ और चौथी कॉलोनी दो एकड़ में काटी जा रही थी। ये कॉलोनियां कृषि भूमि जमीन पर बिना किसी स्वीकृति के काटी जा रही थीं।

वहीं, नगर निगम गुरुग्राम के जोन-चार क्षेत्र की इन्फोर्समेंट टीम ने शुक्रवार को सेक्टर-72 में अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई की। इसके तहत दो भवनों तथा दो डीपीसी स्तर के निर्माणों को तोड़ने के साथ ही दो अन्य भवनों को सील करने की कार्रवाई की गई।

घर में घुसकर महिला से छेड़खानी, विरोध करने पर पिता-भाई को पीटा और की गाली-गलौज

गाजियाबाद के कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर महिला व उसके पिता और भाई को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो आरोपित भाग निकले। मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।

गाजियाबाद। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में घर में घुसकर महिला के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर महिला व उसके पिता और भाई को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए तो आरोपित भाग निकले। मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपितों की

तलाश शुरू कर दी है।
एक गांव के रहने वाले व्यक्ति कामगार
हैं। दो दिन पहले वे परिवार समेत घर पर
थे। इस बीच चार युवक उनके घर का
दरवाजा खटखटाने लगे। व्यक्ति की पत्नी
ने दरवाजा खोला तो आरोपित जबरन घर में
आकर गाली-गलौज करने लगे। महिला के
साथ छेड़खानी शुरू कर दी। चीख सुनकर
व्यक्ति व महिला का भाई वहां पहुंचा और



आरोपितों का विरोध करने लगे। आरोपितों ने की मारपीट

आरोप है कि आरोपितों ने उनके साथ ही मारपीट कर दी। लात-घुसों से उन्हें बेरहमी से पीटा। जाते समय आरोपित पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर गए। पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपित खुद को हिंदू संगठन का पदाधिकारी बताते हैं। मामले में महिला ने आरोपितों के खिलाफ थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की

आरोपी की जल्द गिरफ्तारी होगी

एसीपी मोदीनगर ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि सौरभ शर्मा, रजनीश शर्मा, शुभम और आशीष के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। महिला के बयान दर्ज कराए गए हैं। जल्द आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

विकसित भारत का रोडमैप और देश की आर्थिक सफलता की कहानी है अंतरिम आम बजट

प्रह्लाद सबनार्न

पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत के नागरिकों ने वित्तीय क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव देखे हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किया गया है कि भारत में सर्वसमावेशी, सर्वांगीण एवं सर्वस्पर्शी विकास हो। देश में खाद्यान की चिंता दूर हुई है।

र्षं 2024 में लोक सभा चुनाव होने जा रहे हैं, अतः केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट में भारी भरकम घोषणाओं से बचते हुए दिनांक 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में वोट ओन अकाउंट पेश किया। लोक सभा चुनाव के सम्पन्न होने के पश्चात एक बार पुनः वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट वित्त मंत्री महोदया द्वारा लोक सभा में पेश किया जाएगा। इस तरह से परम्परा का निर्वहन ही किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 वर्ष के लिए पेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 वर्ष के लिए पेश किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 वर्ष के लिए पेश किया गया है। वित्तीय कर्ष 2024-25 वर्ष के लिए पेश किया गया है। वित्तीय क्षं 2024-25 वर्ष के लिए पेश किया गया है। क्षा सुख्य विशेषता यह है कि पूंजी गत व्यय को बढ़ाने के बाव जूद वित्तीय घाटे को कम करने का सफल प्रयास किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए गए केंद्रीय बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया था। इसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट में बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए का कर दिया गया था और अब वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट में 11.11 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। यदि किसी देश में पूंजीगत व्यय की मात्रा बढ़ाई जाती है तो इससे उस देश के लिए आय के

साधन भी बढते हैं। यह तथ्य भारत के मामले में भी उजागर होता दिखाई दे रहा है। पिछले दो वर्षों के दौरान लगातार भारी भरकम राशि के पूंजीगत व्यय के कारण अबदेश की सकल आय में भी वृद्धि दृष्टिगोचर है। न केवल अप्रत्यक्षकर, वस्तु एवं सेवा कर, की औसत मासिक वसूली 1.66 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की हो गई है बिल्क प्रत्यक्ष करों में भी 25 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि दर्ज हो रही है। जिसके चलते केंद्र सरकार को पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के साथ ही वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने में भी सफलता मिल रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से 23.24 लाख करोड़ रुपए की कुल आय अनुमानित है और कुल खर्च 44.90 लाख करोड़ रुपएका अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्तीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का, 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमानलगायागयाहै।वित्तीयवर्ष2024-25 के दौरान प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से कुल आय बढ़कर 30.80 लाख करोड़ रुपए रहने की सम्भावना व्यक्त की गई है तो कुल व्यय 47.66 लाख करोड़ रुपए रहने की सम्भावना है। इस प्रकार वित्तीय घाटा, सकल घरेलू उत्पादका, 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय घाटे को वित्तीयवर्ष 2025-26 में 4.5 प्रतिशत तक नीचे लाने के प्रयासकिए जा रहे हैं।वित्तीय घाटा कम होने का सीधा-सा अर्थहै कि केंद्र सरकार को बाजार से कम ऋग लेने की आवश्यकता होगी क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत खर्च में बढ़ौतरी के चलते आय के साधन बढ़ रहे हैं। इससे भारतीय बैंकों को निजी क्षेत्र को ऋग उपलब्ध कराने हेतु अधिक राशि उपलब्ध होगी। वैसे भी, पिछले दो वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किए गए भारी भरकम पुंजीगत खर्च के चलते देश के आर्थिक चक्र में जो गति आई है उसके कारण उत्पादों की मांग में वृद्धि दर्ज हुई है एवं विभिन्न विनिर्माण इकाईयां



अपनी उत्पादन क्षमता का 75 प्रतिशत से अधिक उपयोग करने लगी हैं। इसस्थिति के बाद सामान्यतः विनिर्माण इकाई यों के लिए अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना आवश्यक हो जाता है। अतः अब उद्योग क्षेत्रको अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी जिसे बैंकों से ऋग लेकर पूरा किया जा सकता है। अतः केंद्र सरकार अपने संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए अभी से यह प्रयास कर रही है कि उसे स्वयं कम ऋग की आवश्यकता हो ताकि यह राशि उद्योग क्षेत्रको ऋग के रूप में उपलब्ध करायी जा सके। इस प्रकार, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने इस बजट के माध्यम से पूंजीगत खर्च को बढ़ाने के बावजूद वित्तीय घाटे को कम करने का सफल प्रयासकिया है। पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत के नागरिकों ने वित्तीय

क्षेत्रमें कई सकारात्मक बदलाव देखे हैं। केंद्र सरकार

द्वारा प्रयास किया गया है कि भारत में सर्वसमावेशी,

सर्वांगीण एवं सर्वस्पर्शी विकास हो। देश में खाद्यान की चिंता दुर हुई है। ग्रामीण इलाकों के प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लगभग एक करोड़ नए मकान निर्मित किए गए हैं, हर घर नल योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में घरों तक पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है एवं मातृशक्ति को कुकिंग गैस उपलब्ध कराई गई है। 50 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं ताकि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे ही इन बैंक खातों के माध्यम सेहितग्राहियों के हाथों में पहुंचे 180 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत 11.8 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष सम्मान निधि सीधे उनके खातों में जमा की जा रही है। 4 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। फसलों की विभिन्न पैदावार पर न्यूनतम

समर्थन मल्य के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। कुल मिलाकर, पिछले 10 वर्षों के दौरान 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने में सफलता मिली है। इससे अब भारतीय नागरिकों की अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। अतः नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करते हुए माननीया वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन नेवित्तीयवर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट में घोषणा की है कि एक करोड़ नागरिकों को, जो सोलर पेनल का उपयोग करेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में प्रदान की जाएगी ताकि भारत में सौर ऊर्जा के उपयोगको बढ़ावा दिया जा सके और पेट्रोल, डीजल एवं कोयले के उपयोग को कम किया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 2 करोड अतिरिक्त नए मकान बनाए जाएंगे ताकि देश के प्रत्येक परिवार के पास अपनी छत उपलब्ध हो

सके। आगे आने वाले कुछ वर्षों में लखपित दीदी बनाने के उद्देश्य से 9 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि मातृशक्ति रोजगार देने वाली बनें। देश में अभी तक एक करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लखपित दीदी बनाया जा चुका है। इस लक्ष्य को अब 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया

देश में अधोसंरचना को विकसित करने के उद्देश्य से रेल्वे के तीन नए कोरिडोर बनाए जाने का प्रावधान भी किया गया है। प्रथम, ऊर्जा, खनिज एवं सीमेंट गलियारा।द्वितीय, पत्तनगलियारा एवं तृतीय अधिक यातायात वाला गलियारा। यह तीन गलियारे पूर्व में ही विकसित किए जा रहे समर्पित माल गलियारे के अतिरिक्त होंगे। इन तीन गलियारों के विकसित होने के बाद देश में रेल्वे की सुविधाओं में और अधिक सुधार होगा। इसी प्रकार देश में हवाई अड्डों की संख्या भी बढ़कर 149 हो गई है एवं अब कई 2 एवं 3 टायर शहरों में भी हवाई अड्डों का निर्माण किया जा चुका है। भारत में कार्य कर रही विभिन्न विमानन कम्पनियों द्वारा 1000 नए विमानों को खरीदने का ऑर्डर दिया जा चुका है। कुल मिलाकर देश में अधोसंरचना के क्षेत्रमें, रोड, रेल, हवाई मार्गएवं जल मार्गसहित, अतुलनीय सुधार हुआ है।

केंद्र सरकार रेविड्यां बांटने के स्थान पर देश में आधारभूत संरचना को विकसित करने पर अधिक जोर दे रही है। इससे देश की सकल आय में वृद्धि हो रही है और युवा, महिला, किसान एवं गरीब वर्ग के हितार्थ नई नई योजनाएं चलाने में आसानी हो रही है। देश के समस्त परिवारों के लिए अपनी छत, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था किए जाने के भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। इससे देश के नागरिकों में विश्वास पैदा हो रहा है। www.newsparivahan.com

बिक्री के लिए उपलब्ध है क्वीन एलिजाबेथ की कस्टम रेंज रोवर, शाही एसयूवी के लिए रखी इतनों पैसों की मांग

ब्रैमली मोटर कार्स की आधिकारिक वेबसाइट पर Queen Elizabeth II की Range Rover के बारे में सभी डिटेल्स साझा की हैं। इस कार को शाही उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था। इसके इंटीरियर में शानदार ब्लैक लेदर और ब्लैक बैज कार्बन फाइबर ट्रिम के साथ जोड़ा गया ब्लैक डायमंड फिनिश है। आइए Queen Elizabeth II की Range Rover के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। Queen Elizabeth II की Range Rover बिक्री के लिए उपलब्ध है। कभी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पसंद रही इस पॉपलर एसयवी को वर्तमान में बैमली नीलामीकर्ताओं के माध्यम से लॉयर ब्लू रंग में सेल किया जा रहा है। इसकी कीमत 379,850 यूरो (लगभग 4,01,41,712 रुपये) रखी गई है । आइए, जान लेते हैं कि ये कीर कितनी खास है।

Queen Elizabeth II की Range

ब्रैमली मोटर कार्स की आधिकारिक वेबसाइट पर Queen Elizabeth II की Range Rover के बारे में सभी डिटेल्स साझा की हैं। इस कार को शाही उपयोग के लिए डिजाइन किया गया था। इसके इंटीरियर में शानदार ब्लैक लेदर और ब्लैक बैज कार्बन फाइबर टिम के साथ जोडा गया ब्लैक डायमंड फिनिश है। इसकी तस्वीरें भी साझा की गई

इसके अलावा ये कार शृटिंग स्टार हेडलाइनर. मसाज सीट्स और ड्राइव असिस्टेंस सिस्टम से लैस है। आइए, इसकी अन्य खासियत के बारे में क्रमवार

इस एसयवी का मल पंजीकरण नंबर अभी भी OU16 XVH है।

ये अभी तक केवल 18,000 मील ही चली है। इसे मार्च 2024 तक किसी सर्विसिंग की आवश्यकता नहीं है।

इसकी कीमत 379,850 यूरो (लगभग 4.01.41.712 रुपये) रखी गई है।



क्या Paytm FASTag 29 फरवरी के बाद नहीं करेगा काम? सभी सवालों के जवाब जो दूर करेंगे आपकी उलझन



Paytm FASTag 29 फरवरी के बाद होगा बंद?

RBI ने 31 जनवरी को एक बड़ा फैसला लेते हुए PPBL की बैंकिंग सेवा पेटीएम पेमेंट बैंक और वॉलेट के लिए डिपॉजिट होना बंद हो जाएगा। इसके साथ ही प्रीपेड कार्ड फास्टैग एनसीएमसी कार्ड आदि में डिपॉडिट क्रेडिट लेनदेन टॉप-अप या निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी क्या आपको फास्टैग भी काम नहीं करेगा।

आइये जानते हैं कि ऐसे में आप क्या कर सकते हैं।

नई दिल्ली।RBI ने पेटीएम और इसके कस्टमर्स को चौकाते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ साथ वॉलेट और कुछ अन्य सर्विसेज को भी बैन कर दिया है. जिसमें पेटीएम फास्टैग भी शामिल है। इसके चलते आप अपने फास्टैग में डिपॉजिट. क्रेडिट लेनदेन. टॉप-अप नहीं कर सकेंगे।

ऐसे में ज्यादातर लोगों के बीच से इस सवाल ने जगह बना ली है कि क्या वो 29 फरवरी के बाद अपने पेटीएम फास्टैग का इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं। आज हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब लेकर आए है।

क्या है बैन का कारण

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत अपने अधिकार के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) को तुरंत नए कस्टमर्स को शामिल करना बंद करने का निर्देश दिया है।

RBI ने नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि 29 फरवरी. 2024 के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड कार्ड, वॉलेट, फास्टैग, NCMC कार्ड आदि में डिपॉजिट, क्रेडिट लेनदेन, टॉप-अप या निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

क्या कर सकते हैं कस्टमर्स कंपनी ने अपनी X पोस्ट के जरिए बताया की अगस्त 2023 से पेटीएम पेमेंट्स बैंक भारत में FASTag का सबसे बड़ा इश्रुअर रहा है। इसके साथ लोग 300 से अधिक शहरों में टोल का भुगतान करें।

कपनी ने बताया कि फास्टैग और NCMC कार्ड में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग, निकासी या ट्रांसफर 29 फरवरी तक पहले जैसा ही किया जा सकता है। हालांकि इन अकाउंट में किसी भी टॉप अप या आगे क्रेडिट की अनुमति केवल 29 फरवरी, 2024 तक ही

ऐसे में एक निश्चित समय के बाद ही सही Paytm FASTag यूजर्स को अपना FASTag बंद करना होगा और यहां तक कि अपने वाहन को भी इससे अलग करना होगा।

Ola S1 X 4 kWh इलेक्ट्रिक स्कूटर 1.10 लाख रुपये की कीमत में हुआ लॉन्च



Ola S1 X 4kWh इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च हो गया है। इसको किफायती कीमत में लॉन्च किया गया है। इस स्कूटर में S1 X लाइनअप का अब तक का सबसे बड़ा बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है। जो सिंगल चार्जिंग में लंबी रेंज देने का वादा करता है। यह S1 X 3 kWh वेरिएंट से लगभग 20000 रुपये अधिक महंगा है। आइए इसके बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली।Ola Electric ने हाल ही में S1 X 4 kWh इलेक्टिक स्कटर वेरिएंट को लॉन्च किया है। इसको किफायती कीमत में लॉन्च किया गया है। इस स्कटर में S1 X लाइनअप का अब तक का सबसे बड़ा बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है। जो सिंगल चार्जिंग में लंबी रेंज देने का वादा करता है। यहां इसकी कीमत और फीचर्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं।

Ola S1 X 4 kWh की कीमत

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 1.10 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। यह S1 X 3

kWh वेरिएंट से लगभग 20,000 रुपये अधिक महंगा है। जबकि एंटी लेवल Ola S1 X 2 kWh टिम की कीमत 79,999 रुपये एक्स शोरूम है। फीचर्स और मोड

Ola S1 X 4 kWh में S1 X 3 kWh वेरिएंट के समान ही मैकेनिकल फीचर्स बरकरार रखे गए हैं। यह महज 3.3 सेकंड में ही 0-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर लेता है। वहीं, इसकी टॉप स्पीड 90 किमी/प्रति घंटा है। इलेक्ट्रिक मोटर 6 किलोवाट 8bhp का उत्पादन जारी रखती है। इसमें तीन राइडिंग मोड प्रदान किए गए हैं जो कि ईको, नॉर्मल और स्पोर्ट हैं। अप्रैल में शुरू होगी डिलीवरी

स्कटर लॉन्च के दौरान कंपनी ने इसकी डिलीवरी के बारे में भी जानकारी दी है। कंपनी ने पुष्टि की कि S1 X 2 kWh और 3 kWh वेरिएंट की डिलीवरी अप्रैल 2024 से शुरू होगी। वहीं, नए S1 X 4 kWh वेरिएंट की डिलीवरी भी अप्रैल में शुरू होगी, इसके टॉप वेरिएंट के लिए कंपनी मौजदा वक्त में बिकंग स्वीकार कर रही है।

महिंद्रा स्कॉरपियो एन, थार और एक्सयूवी ७०० की कीमतों में हुई ५७ हजार रुपये तक की बढ़ोतरी, यहां देखिए नए प्राइस

Mahindra Mahindra की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सबसे बड़ी कीमत बढ़ोतरी XUV700 SUV पर लागू की गई है। 7-सीट कॉन्फिगरेशन और मैनुअल गियरबॉक्स वाले AX7 L पेट्रोल वेरिएंट में 57000 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसिमशन के साथ पेश किया गया डीजल वेरिएंट अब 53000 रुपये तक महंगा हो गया है। आइए अपडेटेड प्राइस लिस्ट के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली।Mahindra ने इस हफ्ते से अपनी फ्लैगशिप एसयुवी Scorpio-N, Thar और XUV 700 को महंगा कर दिया है। कार निर्माता ने तीन एसयूवी के कुछ वेरिएंट पर तत्काल प्रभाव से नवीनतम मूल्य वृद्धि लागू कर दी है। बढ़ती उत्पादन लागत के कारण इस महीने से उसके वाहनों की कीमत अधिक हो जाएगी। ताजा बढ़ोतरी में इन गाड़ियों की कीमत 57,000 रुपये तक बढ़ गई है।

Mahindra XUV 700 की नई की मतें Mahindra & Mahindra की

आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, सबसे बड़ी कीमत बढ़ोतरी XUV700 SUV पर लाग की गई है। 7-सीट कॉन्फिगरेशन और मैनुअल

गियरबॉक्स वाले AX7 L पेट्रोल वेरिएंट में 57,000 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसिमशन के साथ पेश किया गया डीजल वेरिएंट अब 53,000 रुपये तक महंगा हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि नवीनतम अपडेट में एसयुवी के आठ वेरिएंट की कीमतों में भी कमी देखी गई है। पेट्रोल के चार एंट्री-लेवल वेरिएंट की कीमतों में 15,000 रुपये तक की गिरावट देखी गई है। ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और 5-सीट विकल्पों के साथ पेश किए गए AX5 डीजल वेरिएंट पर 21,000 रुपये की सबसे बडी कीमत में गिरावट लाग की गई है। XUV700 की कीमत अब 13.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और टॉप-एंड वेरिएंट के लिए 26.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। इसके सात वेरिएंट्स की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी।

Mahindra Scorpio-N की नई

स्कॉर्पियो-एन और स्कॉर्पियो क्लासिक मॉडल की कीमतों में भी 40,000 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी गई है। दोनों एसयूवी के सभी वेरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है, जो एक को छोडकर, कम से कम 1,000 रुपये से

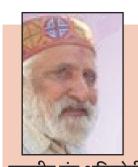
AWD और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ Z8 7-सीटर वेरिएंट की कीमत, जो 23.08 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) में बेची जाती है, अपरिवर्तित बनी हुई है। पेट्रोल और डीजल दोनों संस्करणों में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ Z8 L 6-सीटर पर सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई

जहां पेट्रोल स्कॉर्पियो-एन के एंट्री-लेवल वेरिएंट की कीमत में 34,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, वहीं एंट्री-लेवल डीजल वेरिएंट की कीमत में 24,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। स्कॉर्पियो-एन एसयुवी अब 13.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर आती है और टॉप-एंड वेरिएंट के लिए 24.54 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

Mahindra Thar की नई की मतें Mahindra Thar एसयूवी के सभी वेरिएंट की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। सबसे ज्यादा AX(O) डीजल मैनुअल वेरिएंट पर 35,000 रुपये की बढ़ोतरी के साथ लागू की गई है। ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाले टॉप-एंड पेट्रोल वेरिएंट LX की कीमत भी 34,000 रुपये अधिक होगी। थार एसयूवी की कीमत अब 11.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और 17.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।



विपक्षी गढबंधन में दरारें



कुलदीप चंद अग्निहोत्री

मुझे नहीं लगता मल्लिकार्जुन खड़े की अहमियत पोस्टर से ज्यादा हो। अलबता उनका काम राहुल गांधी की स्वयंकोही नुकसान देने वाली उक्तियों की सकारात्मक व्याख्या कर देने भर तक सीमित हो गया। मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट नहीं होपारहाहै।वह बिखर चुका है'

रअसल विपक्ष में भी एक पक्ष था और दूसरा विपक्ष था। यह इंडी गठबन्धन बनते समय ही दिखाई दे रहा था। क्षेत्रीय दल कांग्रेस को खाकर अपना वजन बढ़ाना चाहते थे और कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को डकार कर अपना वजन बढाना चाहती थी। यह ठीक है कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर लगभग बिखर गई है। यदि केवल सांसदों की संख्या के बल पर ही किसी दल का आकलन करना हो तो उसकी स्थिति भी लगभग किसी बड़े क्षेत्रीय दल के समान ही है। वैसे भी देश के विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय दल मोटे तौर पर कांग्रेस को हाशिए पर धकेल कर ही पैदा हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में एक और तथ्य भी है। बिखरी हुई कांग्रेस का मलबा लगभग सभी राज्यों में इधर-उधर बिखरा पड़ा है। कांग्रेस की इच्छा है कि किसी तरह इस मलबा से फिर से, कम से कम छोटा भवन पुनः बना लिया जाए। बाद में समय मिलने पर उसका विस्तार किया जा सकेगा। लेकिन अब बहुत सीमा तक इस 'मलबा के मालिक' के नाम के तौर पर क्षेत्रीय दलों का नाम चढ़ चुका है। कांग्रेस समझ चुकी है कि वह लडकर यह मलबा वापस नहीं ले सकती। उसने दूसरा रास्ता चुना कि किसी तरह क्षेत्रीय दलों से समझौता कर लिया जाए और उसी समझौते में से बहुत ही चतुराई से जितना मलबा वापस लिया जा सके. कम से कम उतना ले लिया जाए।

www.newsparivahan.com

पैर रखने को जगह मिल जाए तो सिर छुपाने का जुगाड़ भी कर लिया जाएगा। लेकिन उसके लिए जो चतुर मिस्त्री/शिल्पी चाहिए, दुर्भाग्य से कांग्रेस के राज परिवार के पास इस समय वह नहीं है। राहुल गान्धी को जबरदस्ती मिस्त्री का काम करने के लिए धकेला जा रहा है, लेकिन राहुल इसमें सफल हो नहीं रहे। जहां सीमेंट लगाना है, वहां ईंट लगा देते हैं, जहां लकड़ी का काम करना है, वहां शीशा लगाने लगते हैं। अब उनकी सहायता के लिए एक बुजुर्ग मल्लिकार्जुन को भी साथ लगाया गया है। वे बेचारे राहुल को लेकर गली गली घूम रहे हैं। उधर पार्टी चिल्ला रही है, बाबा सिर पर चुनाव है, आप दोनों किस काम में लगे हुए होस लेकिन कोई सुने तब न। राहुल मस्त हैं। बंगाल में हलकान हो रहे हैं। बंगालियो, यदि इस बार भी न जागे तो इतिहास तुम्हें माफ नहीं करेगा। क्षेत्रीय दलों का मसला दूसरी तरह का है। उनको कांग्रेस से भय नहीं है क्योंकि वे जानते हैं कि कांग्रेस अब उनके इलाके में दाखिल नहीं हो सकती। उनकी चिंता भाजपा से है। भाजपा ने जिस प्रकार उत्तरी भारत में जनता को लगभग साथ ले लिया है, उससे उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। वे चाहते हैं कि



उन्हें बचाने के लिए कांग्रेस उनकी मदद करे। जाहिर है कि यदि कांग्रेस मदद करेगी तो बदले में भी कुछ चाहेगी ही। लेकिन क्षेत्रीय दल उसे वह 'कुछ' देने के लिए तैयार नहीं हैं। अलबत्ता यह जरूर कह रहे हैं कि अपने इलाके को छोड़ कर सारे हिंदुस्तान में वे कांग्रेस की मदद करने के लिए तैयार हैं। उदाहरण के लिए पंजाब में हम अकेले भी लड़ लेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस से मिल कर लडेंगे। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि कांग्रेस अपने हिस्से की रोटी में से एक टुकड़ा आम आदमी पार्टी को दे दे, लेकिन पंजाब में उससे रोटी में हिस्सा न मांगे। इस प्रकार हर प्रदेश में टुकड़ा-टुकड़ा रोटी का इकट्ठा करके आम आदमी पार्टी पैन इंडिया पार्टी बनना चाहती है, लेकिन बदले में देने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं। जहां पंजाब में है, वहां उसकी इच्छा है कि कांग्रेस इस इलाके से दूर ही रहे। यही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। यही ममता कर रही है। साम्यवादियों के पास अब देने-लेने के लिए कुछ है ही नहीं। इसलिए वे कांग्रेस के शरीर में घुस कर अंदर से कब्जा करना चाहते हैं। शरीर बाहर से कांग्रेस का ही दिखाई देता रहे, लेकिन अन्दर आत्मा कम्युनिस्टों की कब्जा कर ले। वैसे वे यह प्रयोग पिछले लम्बे अरसे से कर रहे हैं। अबकी बार उनका अपना अस्तित्व ही इस प्रयोग के सफल होने पर निर्भर है। इस प्रयोग की सफलता के लिए वे वाममार्गी हरकतों पर उतर आए हैं । इसीलिए ममता बनर्जी ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा था कि जब भी इंडी गठबंधन की मीटिंग होती है तो उसका नियंत्रण सीता राम येचुरी ही करते लगते हैं। इसी निराकार हालत को देख कर नीतीश बाबू ने एक और प्रयोग कर लेना चाहा।बिहार की राजनीति में वे धीरे-धीरे सिकुड़ते जा रहे थे।

लालू का कुनबा और काम दोनों बढ़ते जा रहे थे। इस स्थिति में या तो लालू नीतीश बाबू को राजनीतिक तौर पर खा जाएंगे या फिर वे स्वतः ही प्रदेश की राजनीति के हाशिए पर चले जाएंगे। प्रदेश की राजनीति में वे चढ़ाव से उतार वाली स्थिति की ओर बढ़ रहे थे। नीतीश बाबू संकट का उपयोग भी लाभदायक ढंग से करने में होशियार माने जाते हैं। उनको लगा यदि सभी विरोधी दलों को एक साथ बिठा लिया जाए और चुनाव के बाद त्रिशंकु लोकसभा आ जाए तो सम्भावनाओं के अपार द्वार खुल सकते हैं। भारतीय राजनीति में इस प्रकार की स्थिति पहले भी पैदा हो चुकी थी। उसी स्थिति में से देवेगौड़ा, चन्द्रशेखर, इन्द्र कुमार गुजराल, चरण सिंह तक प्रधानमंत्री बन गए थे। बस इस प्रकार की हालत में आपकी पार्टी के पास 25-30 सांसद होने चाहिए। इसका एक ही रास्ता नीतीश बाबू को दिखाई दिया। यदि नीतीश और लालू दोनों मिल जाएं तो बिहार में तीस-पैंतीस सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। लाल को प्रधानमंत्री बनने की अब इस उम्र में सेहत के कारण तमन्ना नहीं है। लालू पुत्र बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं और नीतीश बाबू भारत के प्रधानमंत्री। लालू को भी यह सौदा बुरा नहीं लगा। नीतीश बाबू जब प्रधानमंत्री बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश बाबू मुख्यमंत्री का ताज तेजस्वी के सिर पर रख कर दिल्ली चले जाएंगे। नीतीश बाबू भाजपा के एनडीए से निकल कर लालू के साथ चले गए और कांग्रेस व कम्युनिस्टों को साथ लेकर महागठबन्धन बना लिया। सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए दौड़-धूप भी शुरू कर दी। लालू भी अपने बच्चों सहित आगे-आगे चलने लगे। उनके दोनों हाथ घी में। नीतीश प्रधानमंत्री बनें या न बनें. उनका अपना

बेटा तो मुख्यमंत्री बन ही रहा है। यह नीतीश और लालू की दौड़-धूप का नतीजा ही था कि पटना में भांति-भांति के राजनीतिक दल एक दरी पर बैठ कर सांझा फ्रंट बनाने की जुगतें लडाने लगे।

पटना में सभी को एक दरी पर लाकर बिठाने का श्रेय तो लालू-नीतीश को जाता है, लेकिन जब जमने का प्रश्न आया तो झगडा तय था। सामान सीमित था, खाने वाले ज्यादा थे। सभी अपनी अपनी थाली ढकने लगे और कस कर पकड़ने भी लगे। गणित के इस रहस्य की समझ तो सभी को आ गई थी कि जिसके पास 30-40 सांसद हो जाएंगे, उसके भाग्य में देवगौड़ा बनना हो सकता है। कांग्रेस को लगता था अपनी-अपनी थाली से हर कोई दो कौर निकाल कर भी उनकी थाली में डाल देगा तो उनकी हैसियत भी ऐसी हो जाएगी कि वे किसी मनमोहन सिंह को ढूंढने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन दो कौर मांगने की कला भी तो आनी चाहिए। राहुल गान्धी आदेशात्मक लहजे में यह काम करने लगे। मुझे नहीं लगता मल्लिकार्जुन खडग़े की अहमियत पोस्टर से ज्यादा हो। अलबत्ता उनका काम राहुल गान्धी की स्वयं को ही नुकसान देने वाली उक्तियों की सकारात्मक व्याख्या कर देने भर तक सीमित हो गया। सबसे दयनीय स्थिति नीतीश बाबू की हुई। दरी पर बैठी मंडली ने उन पर फोकस किया नहीं और बंगाल में वे लालू के बच्चों के रहमो-करम पर सिमट गए। इसलिए उन्होंने इस चौथ में दरी से उठ जाना ही बेहतर समझा। ममता अभी तक बैठी तो दरी पर ही हैं. लेकिन वहीं बैठे-बैठे दूसरे दरीवानों को धमका रही हैं कि खबरदार किसी ने मेरी थाली की ओर आंख उठा कर भी देखा। मीडिया इसी को इंडी का बिखराव कहता है।

संपादक की कलम से

टोटके का बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी चार महीनों के लिए अंतरिम बजट लोकसभा में पेश किया। यह उनका रिकॉर्ड छठा बजट है। अंतरिम बजट में मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया और अर्थव्यवस्था, विकास की हरी-हरी तस्वीर पेश की गई। मसलन-भारत विश्व-गुरु के तौर पर उभर रहा है। जनता खुश है और सशक्त हुई है। उसमें उम्मीद और आशावाद जागा है। सरकार के 10 सालों में सकारात्मक अर्थव्यवस्था रही है। रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी हुई है। सामाजिक समावेश का आर्थिक विकास हुआ है। भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद खत्म हुआ है। भारत 2047 में 'विकसित राष्ट्र' होगा। अंतरिम बजट से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को आम चुनाव जीतने की कोई चिंता नहीं है, लिहाजा वित्त मंत्री ने दावा किया है कि जुलाई के पूर्ण और आम बजट में विकसित भारत के व्यापक विकास का रोड-मैप पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट में किसी महत्त्वपूर्ण और नई परियोजना की घोषणा नहीं की गई है और न ही आयकर-व्यवस्था में कोई बदलाव किया गया है। फिर भी कुछ घोषणाएं ऐसी हैं, जो मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार हैं, लेकिन उनमें लोकलुभावन भाव भी निहित है। सरकार ने आगामी 5 साल में 2 करोड़ पक्के घर बनाने की घोषणा की है, जबिक 3 करोड़ घर बनाने का दावा किया गया है। अंतरिम बजट में 5 साल की योजना की घोषणा की प्रासंगिकता कितनी है ? जाहिर है कि भाजपा आगामी सत्ता को लेकर भी आश्वस्त है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 70 फीसदी मकानों का स्वामित्व महिला के नाम है। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में बताया है कि एक करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बना दिया गया है और आगे 3 करोड़ को 'लखपित' बनाने का

लक्ष्य तय किया गया है। यह मोदी सरकार की 'महिला सशक्तिकरण' की राजनीति को सत्यापित कर्ती है।

सरकार के 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी-मुक्त किया गया है और यह सरकार की प्रतिबद्धता है। इसके मायने हैं कि देश में गरीबी-रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या नगण्य हो गई है। लेकिन यह हकीकत नहीं है। बहरहाल 43 करोड़ को 'मुद्रा ऋग' के तहत 22.57 लाख करोड़ रुपए के कर्ज मुहैया कराए गए हैं। स्वरोजगार के लिए 34 लाख करोड़ रुपए के कर्ज भी दिए गए। इनमें 78 लाख रेहड़ी-पटरी वाले भी हैं, जिन्हें आर्थिक मदद दी गई है। बेशक मोदी सरकार ने किसानों पर खजाने लुटाए हैं, लेकिन फिर भी बजट में कहा गया है कि किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। करीब 12 करोड़ किसानों को सरकार ने कर्ज मुहैया कराए हैं। फसल बीमा योजना का लाभ 4 करोड़ से अधिक किसानों को मिला है। दरअसल 'मुद्रा लोन' का घोषित आंकड़ा सवालिया है, क्योंकि पूरे भारत में 26-27 करोड़ परिवार बसते हैं। फिर 43 करोड़ को यह ऋग कैसे दिया जा सकता है? आंगनबाड़ी बहनों की घोषणा भी सवालिया है। एक तरफ उन सेविकाओं को सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया जाता। वे मानदेय के नियमित भुगतान को लेकर अक्सर सडक़ों पर प्रदर्शन करने को बाध्य हैं, लेकिन दूसरी ओर उन सभी बहनों को 'आयुष्मान कार्ड' देने की घोषणा की गई है। अंतरिम बजट में 3 रेल कॉरिडोर बनाकर आर्थिक विकास करने की घोषणा की गई है। 'वंदे भारत' में 41,000 रेल डिब्बे शामिल किए जाएंगे। रक्षा क्षेत्र को ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। बजट में पर्यटन, हरित विकास, प्रदूषणरहित ईंधन, जनसंख्या नियंत्रण व 'स्किल इंडिया' योजनाओं की घोषणा भी है।

राय

स्थानांतरणों के मंतव्य

हिमाचल में ताबड़तोड़ तरीके से हो रहे स्थानांतरण के बीच एक गूंज यह कि प्रशासन का निजाम बदल रहा है, दूसरी ओर आगामी लोकसभा चुनाव से पूर्व सरकार ने सारी स्लेटको साफ करके, लोकतांत्रिक फर्ज को वरीयता दी है। धीरे-धीरे जिलों के प्रशासनिक, पुलिस अधिकारी तथा उपमंडल स्तर तक एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदारों की अदला बदली कर दी है। अधिकारियों की नई पांत बिछा कर सक्ख सरकार ने दरअसल अपनी हुकूमत के पत्ते खोले हैं।एक साल की सरकार ने स्थानांतरणों की बड़ी इबारत लिखने से पूर्व संयम बरता और यह आभास नहीं होने दिया कि सत्ता बदलते सभी कुछ बदल गया । इस दौरान ट्रांसफर हुए जरूर, लेकिन आवश्यकता की परख में ही आदेश हुए। बहरहाल ट्रांसफर से प्रशासनिक हुलिया बदलने की खबर है और यह एक नया इम्तिहान भी है सरकार की नीतियों को सफल बनाने और सुशासन की कलम से नया लिखने का। दरअसल सरकार ने राज्य की व्यवस्था को अपने पैमानों और पहरों के तहत दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया है, उम्मीद है यही संदेश विभागीय परतों के परिदृश्य में नए सजावट और नई लिखावट लाएगा । हालांकि ये तमाम स्थानांतरण एक तरह के विशेषााधिकार के तहत सरकार कर रही है, जबिक वर्षों बाद भी न इसकी नीति व नियमों में कुछ नया दर्जहुआ या पारदर्शिता के साथ 'ट्रांसफर आर्डर' को विश्वसनीयता से देखा गया। ये तमाम बड़े साहबों के स्थानांतरण हैं, जिन्हें शहरी आवरण में समझा जा सकता

बड़े साहबों की कोठियां हर स्थानांतरण के बाद भी सह्लियतों के हिसाब से परिपूर्ण रहती हैं, जबिक कर्मचारियों के ट्रांसफर आर्डर कुछ भिन्नता के साथ, राजनीतिक मेलजोल की पारंपरिक रिवायत को निभाते हैं। ग्रामीण स्तर के कार्यालयों, स्कूल-चिकित्सालयों के रिक्त पदों और सार्वजनिक क्षेत्र के सेवा स्तर पर टांसफर के मानदंड किसी मानक के बजाय एक ऐसी फेहरिस्त में सिक्रय हैं, जो दो कर्मचारियों, दो अध्यापकों, दो डाक्टरों या अन्य पदों पर दो कर्मचारियों-अधिकारियों की आपसी सहमित पर म्यूचुअल धरातल पर अदला-बदली खेलते रहते हैं।हिमाचल में स्थानांतरण के मापदंड साबित करते हैं कि सत्ता में किसी अधिकारी-कर्मचारी का फलक क्या है। अब तो सत्ता के बीच विशेषाधिकार प्राप्त कर्मचारी-अधिकारी भी प्रत्याशित तरीके से पदों पर देखे जाते हैं। इसलिए स्थानांतरण से गंतव्य नहीं, मंतव्य साबित होता है। हम जान सकते हैं कि फलां आईएएस या एचएएस अधिकारी ही क्यों किसी जिला की बागडोर संभाल रहा है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि बटालियन में भेजा गया पुलिस अधिकारी क्यों पटरी नहीं बिछा पाया। यही वजह रही है कि पिछली सरकार में एक जिला पुलिस अधिकारी को मुख्यमंत्री के निजी सुरक्षा अधिकारी से उलझते देखकर जनता सहम गई थी। एक यह भी प्रमाण है कि सारे अधिकारी अब व्यवस्था में 'अपनी-अपनी' सरकार खोज रहे हैं। प्रशासन के तत्व, राजनीतिक पहुंच के आगे शून्य हो सकते हैं, लेकिन वीआईपी कारवां जब चलता है तो यह सफर अब नेताओं को नायक और अधिकारियों के हुजूम को तलवे चाटता देखता है। होते हैं कभी कुछ कडक़ पुलिस अधिकारी जो अपराध को खींच लाते हैं बाहर या नशे के सौदागरों को जमीन पर सुला देते हैं, लेकिन अधिकांश कानून व्यवस्था को बदनाम नहीं करते। ऐसे भी एसएचओ स्तर के अधिकारी कामयाब हो जाते, जो जुर्म के पन्नों को खारिज करके सिर्फ ट्रैफिक चालान के पर्याय बन जाते हैं।

भूपिंदर सिंह

खिलाड़ी को तैयार करने में प्रशिक्षक की भूमिका जब जरूरी है तो फिर हम उसे सामाजिक-आर्थिक रूप से निश्चित कर प्रशिक्षण पर केन्द्रित क्यों नहीं होने देते

उय में खेल विभाग बनने के बाद आज तक कई सरकारें आईं, मगर खेल विभाग के हाल नहीं सुधरे हैं। दशकों से हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षकों से अन्याय हो रहा है। कहा गया कि प्रशिक्षक कैडर के भर्ती व पदोन्नति नियमों में सुधार कर लिया है, मगर अभी तक जुनियर प्रशिक्षक का स्केल और काम जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी का लिया जा रहा है। इस विषय पर इस कॉलम के माध्यम से बार-बार सरकार को चेताया कि राज्य में प्रशिक्षकों का स्तर ऊंचा किए बिना खेलों में उत्कृष्टता हासिल नहीं की जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी करोड़ों लोगों में स्वयं व अपने देश को पदक जीत कर सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करता है तो उसके पीछे जहां उस दृढ़ संकल्प, लगातार कठोर परिश्रम व अपनों की सहायता व दुआएं होती हैं, वहीं पर एक प्रशिक्षक की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अलग से राज्यों में खेल विभागों का गठन हुआ है। 1982 के एशियाड़ के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी प्रदेश में हिमाचल प्रदेश युवा सेवाएं एवं खेल विभाग का गठन किया। विभाग के गठन के चार दशक बाद भी अभी तक हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षकों के भर्ती व पदोन्नति नियमों को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है ।

हिमाचल प्रदेश के इस विभाग में निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारियों, प्रशिक्षकों, कनिष्ठ प्रशिक्षकों व युवा संयोजकों के पद सृजित हैं। इस विभाग का कार्य प्रदेश में युवा

गतिविधियों व खेलों का विकास करना है। हिमाचल प्रदेश में यह विभाग खेल प्रशिक्षण खेलों के लिए आधारभूत ढांचा व राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता होने पर नगद पुरस्कार व अवार्ड देने के लिए बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के इस विभाग का निदेशक प्रशासनिक सेवा से ही अधिकतर नियुक्त होता रहा है, केवल विशेष परिस्थितियों में ही आज तक दो बार ही विभागीय अधिकारी निदेशक पद तक पहुंच पाए हैं। उपनिदेशक और कभी-कभी संयक्त निदेशक पद तक विभाग के प्रशिक्षक व युवा संयोजक पदोन्नत होकर पहुंच जाते हैं। इन विभागीय अधिकारियों को अधिक तकनीकी जानकारी होती है। आजकल हिमाचल प्रदेश यवा सेवाएं एवं खेल विभाग के पास कोई भी उपनिदेशक नहीं है। वरिष्ठ जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी को उपनिदेशक के पद पर बिठा कर काम चलाया जा रहा है। नियमित जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी भी केवल कुछ ही जिलों में हैं, शेष जिलों में कामचलाऊ अधिकारी बिठा रखे हैं। सरकार को चाहिए कि जल्दी ही उपनिदेशक के पद पर नियमित पदोन्नति की जाए तथा जिलों में भी नियमित अधिकारी हों। इस समय जो प्रशिक्षक जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी के पद पर तदर्थ कार्य कर रहे हैं, उन्हें एकमुश्त नियमों में छूट देकर नियमित अधिकारी बना दिया जाए। इस विषय पर पहले भी इस कॉलम के माध्यम से लिखा जा चुका है, मगर लगता है कि सरकार के लिए युवा शक्ति व खेल प्राथिमकता पर नहीं हैं।विभाग में नाममात्र के प्रशिक्षक हैं। अधिकतर खेलों में तो एक भी प्रशिक्षक पूरे जिले के लिए उपलब्ध नहीं है। विभाग में जो प्रशिक्षक नियुक्त हैं उन्हें कनिष्ठ प्रशिक्षक के पद पर नियुक्ति मिली है। उसके बाद वे सेवानिवृत्ति तक भी प्रशिक्षक नहीं

विभाग में नियुक्त प्रशिक्षकों को जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी पद पर पदोन्नति के

प्रशिक्षकों के साथ अन्याय क्यों?



लिए केवल 25 प्रतिशत ही कोटा है।50 प्रतिशत युवा संयोजक व 25 प्रतिशत पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाते हैं। प्रशिक्षक बनने की योग्यता बहुत कठिन है। स्नातक डिग्री के साथ जो प्रतिभागी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हो या तीन बार वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया हुआ हो या शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में खेला हो, उसके बाद राष्ट्रीय क्रिड़ा संस्थान में प्रवेश परीक्षा पास कर एक वर्ष के कठिन प्रशिक्षण व शिक्षण के बाद प्रशिक्षक बनता है। सेवा नियमों में एक समय एमपीएड के साथ कंडैंस कोर्स, जो छह माह का होता था, उसे पास किया हुआ प्रशिक्षक के पद के लिए योग्य था, मगर अब ऐसा कोई नियम नहीं है । हिमाचल प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह प्रदेश में नियुक्त कनिष्ठ प्रशिक्षकों को पांच साल के बाद प्रशिक्षक के पद पर पदोन्नत कर 50 प्रतिशत कोटा जिला अधिकारी पद पर पदोन्नति के लिए

दिया जाए, क्योंकि प्रशिक्षकों की संख्या बहुत अधिक है। अगर हर खेल में जिला स्तर पर पांच प्रशिक्षक भी हों तो प्रशिक्षकों की संख्या सौ से भी अधिक जा सकती है। इसके मुकाबले बारह जिलों में बारह ही युवा संयोजक नियुक्त हैं। इस तरह देखा जाए तो यह प्रशिक्षकों के साथ बहुत अन्याय है। प्रदेश में विभिन्न खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्ले फील्ड तो बन कर तैयार हैं, मगर उनका न तो सही रखरखाव है और न ही उन पर उस स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम

सरकार को चाहिए कि वहां पर उन खेलों में उच्च प्रदर्शन करवाने वाली खेल अकादिमयां स्थापित की जाएं। हिमाचल प्रदेश में युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के दो खेल छात्रावास बिलासपुर व ऊना में कुछ चुनिंदा खेलों के लिए कामचलाऊ प्रशिक्षण प्रबंध तो है, मगर उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाने वाले प्रशिक्षकों की कमी व प्रबंधन में अव्यवस्था साफ देखी जा सकती है। उत्कृष्ट खेल परिणाम दिलाने वाले प्रशिक्षक

बहुत कम हैं। क्योंकि विभाग में प्रशिक्षकों की अनदेखी जिसमें बहुत कम ग्रेड पे व दशकों से कनिष्ठ पद पद पर कार्यरत रहने के कारण राष्ट्रीय क्रीडा संस्थान से प्रशिक्षित प्रशिक्षक खेल विभाग में प्रशिक्षक बनने से अधिक शिक्षा विभाग में प्राध्यापक या डीपीई बनने को अधिमान देते हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाने के लिए प्रशिक्षकों व खिलाडियों के लिए एक अच्छी प्रबंधन टीम की अहम भूमिका है। सही प्रबंधन मिले, इसके लिए नियमित जिला खेल अधिकारियों, उपनिदेशकों, प्रशिक्षकों, अन्य अधिकारियों की नियुक्ति जरूरी है। खिलाड़ी को तैयार करने में प्रशिक्षक की भूमिका जब बेहद जरूरी है तो फिर हम उसे सामाजिक व आर्थिक रूप से निश्चिंत कर शारीरिक व मानसिक पूरी तरह अपने प्रशिक्षण पर केनद्रत क्यों नहीं होने देते। इसलिए राज्य के युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में प्रशिक्षकों के साथ न्याय करने के लिए इनके भर्ती व पदोन्नति नियमों में संख्या अनुपात में संशोधन करना बहुत जरूरी है।

हास्य रस



कुर्सी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है

परतंत्र भारत में लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजों से साफ शब्दों में कहा था कि 'स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा।' इसके बदले मिली उनको असंख्य यातनाएं और जेल यात्राओं की अनवरत त्रासिद्यां। लेकिन वे अपनी बात से अंतिम समय तक नहीं हटे तथा आजादी की अलख को जलाए रखा। उस समय ऐसे ही नेताओं की भरमार थी, जो भारत माता को परतंत्रता की बेडियों से मुक्त कराने के लिए हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। उन्हें अपने देश से असीम प्रेम था। आज का नेता भी इस मामले में कहां कम है। बस उस समय आजादी की चाहना थी और आज कुर्सी की। आज के नेता का यही कथन है कि कुर्सी मेरा जन्मसिद्ध

अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। पहले भारत के लिए मर मिटने की तमन्ना थी और अब कुर्सी के लिए कुछ भी कर गुजरने की लालसा है। बस चाहनाएं बदली हैं, बाकी नेताजी उस समय के नेताओं से कहां पीछे हैं। कुर्सी पर जन्मसिद्ध अधिकार का मतलब नेताजी का इस बात से है कि अब राजनीति में वंशवाद की विषबेल तेजी से फल-फूल रही है। नेता का बेटा नेता ही बनता है, वह कोई दूसरा व्यवसाय या धंधा नहीं अपनाता। एक बार तो राजनीति में आ गया, बाद में उसका बेटा या बेटी, भाई या बहन, पत्नी या साला अथवा भतीजे-भतीजी आराम से प्रवेश कर गए हैं। उसे राजनीति के लिए किसी खास पृष्ठभूमि तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। पृष्ठभूमि यही है कि उनके पिताजी, काकाजी या जीजाजी ने पोजीशन ले ली है, उसके आधार पर वे सीधे ही सांसद या विधायक का टिकट प्राप्त कर लेते हैं।

टिकट मिलने के बाद कुर्सी कोई ज्यादा दूर नहीं रहती। कुर्सी चलकर उनके पास आ जाती है। जब कुर्सी आ जाती है तो वे कुछ भी अवैध कार्य करने को स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र भारत में रहकर राजनीति का धंधा कर रहे हैं। कुर्सी की प्राप्ति के लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, करते हैं। पता नहीं कितनी बार दल बदलते हैं। यही अवसरवादिता तो उन्हें कुर्सी दिलवाती है। चुनाव जीतने के लिए साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, जातीयता तथा भाषावाद, जिसकी भी आवश्यकता है, उसका आसरा लेते हैं। नए-नए गठबंधन, नए से नए गठजोड़ और तालमेल तथा नए से नया समीकरण कुर्सी हथियाने के गुर हैं। राजनीति में जो जितना गिरता है, वह उतना ही ऊंचा उठता चला जाता है। चुनाव जीतने के जितने भी तरीके हैं, उनके लिए करोड़ों रुपयों की आवश्यकता होती है, नेताजी इसके लिए घोटालों पर घोटाले करते चले जाते हैं। भ्रष्टाचार उनके दोनों हाथों का नायाब खेल है। जांच आयोग बैठ जाए तो नेताजी के कैरियर में चार चांद लग जाते हैं। वे बराबर सुर्खियों में बने रहकर अपनी प्रतिभा के तेज से जनमानस की आंखों को चुंधियाते रहते हैं। क्योंकि पहली बात तो जांच आयोग की रिपोर्ट वर्षों तक आती नहीं और मामले न्यायालयों में लिम्बत चलते रहते हैं और यदि रिपोर्ट आ भी जाती है तो वह टांय-टांय फिस्स होती है। उसमें नेताजी साक्ष्यों के अभावों में बेदाग और निर्दोष पाए जाते हैं। जितने भी मामले अब तक हुए हैं, उन पर दृष्टिपात कर देख लीजिए। किसी नेता का आज तक बाल भी बांका नहीं हुआ है, क्योंकि ज्यादातर नेता गंजे होते हैं। गंजे पर शर्म का पानी ठहरता नहीं, चाहे चीनी, चारा, यूरिया, बोफोर्स या हवाला का मामला बनाम घोटाला हो, तमाम नेता देश के कर्णधार बने हुए हैं। अग्रिम बेल मिल जाती है और उनकी कुर्सी ज्यों की त्यों बनी रहती है, क्योंकि कुर्सी उनके जन्मसिद्ध अधिकार में सम्मिलत है, तो वह भला छीनी भी कैसे जा

पूरन सरमा

1(1/1/11

इनसाइड

अब एफिल टॉवर घूमना होगा और भी आसान, UPI पेमेंट के जरिए कर सकेंगे टिकट बुक



भारतीय अब पेरिस के एफिल टॉवर देखने के लिए एकीकृत भुगतान इंटरफेस(UPI) का उपयोग करके टिकट बुक कर सकेंगे। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स (NIPL) ने फ्रेंच ई-कॉमर्स और प्रॉविसमिटी पेमेंटस लायरा के साथ साझेदारी की है जो यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि यूरोपीय देश में यूपीआई भुगतान तंत्र स्वीकार किया जाएं। आइये इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

मुंबई। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने शुक्रवार को कहा कि पेरिस के एफिल टॉवर देखने आने वाले पर्यटक अब भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस(UPI) का उपयोग करके प्रतिष्ठित स्मारक की अपनी यात्रा बुक कर सकेंगे।

एनपीसीआई ने कहा कि उसकी शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंटस (NIPL) ने फ्रेंच ई-कॉमर्स और प्रॉक्सिमटी पेमेंट्स लायरा के साथ साझेदारी की है, जो यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि यूरोपीय देश में यूपीआई भुगतान तंत्र स्वीकार किया

UPI के जरिएखरीद सकेंगे टिकट

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि भारतीय पर्यटक अब यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) का उपयोग करके ऑनलाइन टिकट खरीदकर एफिल टॉवर की अपनी यात्रा बुक कर सकते हैं, जिससे लेनदेन प्रक्रिया त्वरित, आसान और परेशानी मुक्त हो जाएगी।

आपको बता दें कि यह घोषणा भारत के गणतंत्रदिवस का जश्न मनाने के लिए फ्रांस में भारतीय दुतावास द्वारा पेरिस में आयोजित एक कार्यक्रम में की गई थी।

इसमें कहा गया है कि वर्तमान में, भारतीय पर्यटक एफिल टॉवर देखने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के दूसरे सबसे बड़े समृह में हैं। भारतीय पर्यटक बस वेबसाइट पर जनरेट क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान कर

एफिल टॉवर फ्रांस में यूपीआई भुगतान की पेशकश करने वाला पहला बिजनेस है. और यह सेवा जल्द ही फ्रांस और युरोप में पर्यटन और खुदरा क्षेत्र के अन्य बिजनेस तक

विस्तारित की जाएगी। क्यों किया गई ये पहल

एनआईपीएल के मुख्य कार्यकारी रितेश शुक्ला ने कहा कि ये युनिट एक इंटरऑपरेबल वैश्विक भगतान प्रणाली बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एनपीसीआई के भुगतान समाधानों की स्वीकृति को सक्षम

जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों में बढ़ोतरी की पूरी गुंजाइश अगले दो साल में 10 करोड़ तक जा सकता है ITR का आंकड़ा

www.newsparivahan.com

इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत करदाताओं को आयकर में और छट की उम्मीद पर मल्होत्रा ने बताया कि अभी पिछले साल ही इस व्यवस्था के तहत टैक्स छट का एलान किया गया था। अभी इसका एक वर्ष ही हुआ है। कर स्थायित्व के लिए कुछ समय तक इसके प्रभाव को देखना पड़ेगा। चालू वित्तं वर्ष में जीएसटी का मासिक संग्रह 1.85 लाख करोड को पार कर सकता है।

नई दिल्ली। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों की बढ़ोतरी में पूरी गुंजाइश है और सरकार टेक्नोलाजी का इस्तेमाल कर इस दिशा में आगे बढ़ रही है। उनका मानना है कि आगामी दो वर्षो में इनकम टैक्स रिटर्न (आइटीआर) भरने वालों की संख्या 10 करोड़ के स्तर को छू सकती है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 में आइटीआर भरने वालों की संख्या आठ करोड़ के आंकड़ों को पार कर चुकी

प्रत्यक्ष कर में 13 प्रतिशत बढ़ोतरी का अनुमान

. उन्होंने बतायाँ कि आगामी वित्त वर्ष 2024-25 में प्रत्यक्ष कर में 13 प्रतिशत तो अप्रत्यक्ष कर में 12.5 प्रतिशत की बढोतरी का अनुमान है और इस हिसाब से टैक्स के कुल संग्रह में अगले वित्त वर्ष में 11.5 प्रतिशत की बढोतरी रहेगी। दैनिक जागरण को दिए साक्षात्कार में मल्होत्रा ने बताया कि अभी यह देखा जा रहा है कि वस्तु की बिक्री व वस्तु की खरीदारी में मेल नहीं है। जितनी वस्त की बिक्री दिखाई जा रही है, उतनी खरीदारी नहीं दिखाई जा रही है।

वित्त वर्ष में 1.85 लाख करोड़

कुछ जायज तो कुछ नाजायज कारणों से यह मिलान नहीं हो पा रहा है। हम इसको रोकेंगे। अभी कई वस्तुएं जीएसटी के दायरे में नहीं है, हम उसे भी लाने का प्रयास करेंगे। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी का औसत मासिक संग्रह 1.68 लाख करोड़ है जो अगले वित्त वर्ष में 1.85 लाख करोड़ को पार कर सकता है।

इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के तहत करदाताओं को आयकर में और छूट की उम्मीद पर मल्होत्रा ने बताया कि अभी पिछले साल ही इस व्यवस्था के तहत टैक्स छट का एलान किया गया था। अभी

इसका एक वर्ष ही हुआ है। कर स्थायित्व

के लिए कुछ समय तक इसके प्रभाव को

देखना पड़ेगा। पूर्ण बजट में आयात शुल्क में किए जा सकते हैं बदलाव

बजट में मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़े कई आइटम के आयात शुल्क में कटौती की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन ऐसा नहीं होने के बारे में पछे जाने पर राजस्व सचिव ने कहा कि जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में वस्तुओं के आयात शुल्क में जरूरत के मृताबिक बदलाव किए जा

Income Tax

सकते हैं। उन्होंने कहा कि बजट से ठीक पार्ट्स के आयात शुल्क में कटौती की

एक दिन पहले ही हमने मोबाइल फोन के

चुनौतियों के बावजूद भारत दुनिया का उज्ज्वल स्थान बना रहेगा: पीयूष गोयल



वाणिज्य मंत्री ने कहा कि एफटीए करते समय सरकार सनिश्चित करती है कि सभी शर्तें भारत के लिए सर्वोत्तम हों। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं ने प्रत्यक्ष

विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रभावित किया है लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भारत विदेशी कंपनियों के लिए दुनिया का उज्ज्वल स्थान बना रहेगा। गोयल ने कहा

वैश्विक अनिश्चितता ने निश्चित रूप से एफडीआई को प्रभावित किया है।

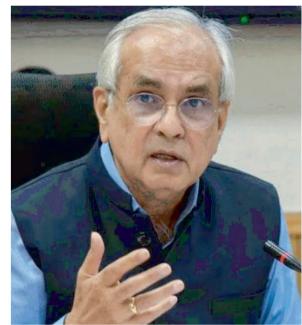
नर्ड दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयष गोयल कहा कहना है कि वैश्विक निवेश (एफडीआई) को प्रभावित किया है, दूर रखा है।

लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भारत विदेशी कंपनियों के लिए दुनिया का उज्ज्वल स्थान

गोयल ने कहा कि मक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) या द्विपक्षीय निवेश संधियों (बीआइटी) पर हस्ताक्षर करते समय सरकार हमेशा यह सुनिश्चित करती है कि सभी शर्तें भारत के लिए सर्वोत्तम हों। गोयल ने कहा, 'वैश्विक अनिश्चितता ने निश्चित रूप से एफडीआइ को प्रभावित किया है, खासकर यह देखते हुए कि अमेरिका तथा अन्य विकसित देशों में ब्याज दरों में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी देखी गई है। मंत्री ने कहा कि भारत की आकांक्षी आबादी और अन्य समर्थक हमें यह विश्वास दिला रहे हैं कि सभी प्रतिकलताओं के बावजद भारत वृद्धि करना जारी रखेगा।' स्टार्टअप के लिए कर प्रोत्साहन बढ़ाने के प्रस्ताव के प्रभाव पर पूछे जाने पर गोयल ने कहा कि इसका मकसद देश के स्टार्टअप परिवेश को प्रोत्साहित करना है।

कर या आयात शुल्क में बदलाव न करने के वित्त मंत्री के फैसले पर गोयल ने कहा. 'यह उचित है कि उन्होंने रियायतें देने या दरों आर्थिक अनिश्चितताओं ने प्रत्यक्ष विदेशी) में कोई बदलाव करने के प्रलोभन से खुद को

राजकोषीय नजरिये से सूझबूझ वाला है अंतरिम बजट: बेरी



नीति आयोग के उपाध्यक्ष बोले सरकार वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेगी। सुमन बेरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के चुनाव-पूर्व अंतरिम बजट को राजकोषीय नजरिये से सूझबूझ वाला बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल के बजट का राजकोषीय परिणाम अनुमान से बेहतर है। आइये इसके बारे में जानते हैं।

नई दिल्ली। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के चुनाव-पूर्व अंतरिम बजट को 'राजकोषीय नजरिये से सूझबूझ' वाला बताया। उन्होंने कहा कि सरकार वर्ष 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने में सफल रहेगी। बेरी ने कहा कि अंतरिम बजट एक नया आधार तैयार करता है और जुलाई में पेश किए जाने पूर्ण बजट के बारे में संकेत देता है।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि

इस साल के बजट का राजकोषीय परिणाम अनमान से बेहतर है। उन्होंने कहा, 'हम 2025-26 के लिए 4.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने जा रहे हैं क्योंकि यह सार और संकेत दोनों ही नजरिये से अहम है।' सरकार ने अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटे को अगले वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद का 5.1 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2025-26 में 4.5 प्रतिशत

तक लाने की मंशा जताई है। निजी निवेश दोबारा शुरू होने के संकेत

बेरी ने कहा कि निजी निवेश दोबारा शरू होने के कई संकेत दिख रहे हैं। अगले वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय पर उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो गई थी, लिहाजा पूंजीगत व्यय पर जोर दिया जा रहा है। यह पूछे जाने पर कि बजट में घोषित उपाय अधिक नौकरियां पैदा करने में किस तरह मददगार होंगे, उन्होंने कह कि मुद्दा नौकरी नहीं है, मुद्दा अच्छी नौकरियां हैं।

भारत में नौकरियों के अनुरूप कर्मचारियों का मिलना मुश्किल हो रहा है।' उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों को जरूरी बताते हुए कहा कि प्रक्रियागत सुधार मुश्किल हैं जिनमें से कछ को राज्यों के स्तर पर अंजाम देना

ग्राहकों के गिरते भरोसे को थामने में जुटा पेटीएम, 29 फरवरी के बाद भी काम करता रहेगा पेटीएम ऐप

आरबीआई की ओर से 29 फरवरी के बाद नये ग्राहक जोडने ग्राहकों की तरफ से नई राशि स्वीकार करने प्रीपेड भुगतान के लिए इस्तेमाल में लाये जाने या फास्टटैग में इस्तेमाल पर रोक के निर्देश के बाद मुसीबत में फंसे पेटीएम ने ग्राहकों को सबकुछ सामान्य होने का भरोसा दिया है। फिलहाल पेटीएम को लेकर अविश्वास इतना है कि लोगों ने इसके ऐप को डिलीट करना शुरू कर

नर्ड दिल्ली।नियमों के अनुपालन में कोताही के कारण आरबीआई की ओर से 29 फरवरी के बाद नये ग्राहक जोड़ने, ग्राहकों की तरफ से नई राशि स्वीकार करने, प्रीपेड भुगतान के लिए इस्तेमाल में लाये जाने या फास्टटैग में इस्तेमाल पर रोक के निर्देश के बाद मुसीबत में फंसे पेटीएम ने ग्राहकों को सबकुछ सामान्य होने का भरोसा दिया है।

यह और बात है कि निवेशकों से लेकर ग्राहकों तक में फिलहाल पेटीएम को लेकर

अविश्वास इतना है कि एक तरफ लोगों ने इसके एप को डिलीट करना शुरू कर दिया है और इस्तेमाल भी करने से कतरा रहे हैं। ऐसे में पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने इसके ग्राहकों को आश्वस्त करने की कोशिश की है और कहा है कि पेटीएम एप 29 फरवरी, 2024 के

वन97 कम्यूनिकेशंस

इस भरोसे से ग्राहक कितने संतष्ट होते हैं यह समय बताएगा लेकिन निवेशक समुदाय उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। पेटीएम की प्रवर्तक कंपनी वन97

बाद भी काम करता रहेगा।

लिमिटेड के शेयरों मे गिरावट

कम्यूनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों मे गिरावट का दौर 02 फरवरी को भी जारी रहा। कारोबार की शुरुआत में ही इसके शेयरों के भाव 20 फीसद तक (लोकर सर्किट से भी नीचे) गिर गये थे। उसके बाद से इसके शेयरों की कीमतों में 36 फीसद की



गिरावट दर्ज हो चकी है।

कभी भारत की सबसे सफल स्टार्टअप मानी जाने वाली इस कंपनी के वर्ष 2021 में शेयर बाजार में कदम रखा था और उसके बाद से इसके शेयरों की कीमत 77 फीसद

तक नीचे आ चुकी है। हालांकि कंपनी की तरफ से बताया गया है कि ग्राहकों को खास चिता करने की जरूरत नहीं है।

29 फरवरी के बाद जारी होंगे नियम इसकी सेवाएं 29 फरवरी के बाद भी

मौजुदा शेष राशि का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं। साथ ही पेटीएम के एसोसिएट बैंक के संबंध में आरबीआई के हाल के निर्देश इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स या एनपीएस में पेटीएम मनी लि. (पीएमएल) के

जा रही ज्यादातर सेवाएं सिर्फ

असोसिएट बैंक के साथ ही नहीं

भागीदारी में हैं। पेटीएम को सूचित

किया गया है कि इससे यूजर्स के

बचत खातों, वालेट्स, फास्टैग्स

और एनसीएमसी खातों में जमा

राशि प्रभावित नहीं होगी। इनमें वे

बल्कि विभिन्न बैंकों के साथ

परिचालन या ग्राहकों के निवेश को प्रभावित नहीं करेंगे। पेटीएम की दूसरी वित्तीय सेवाएं, जैसे कि ऋग वितरण एवं बीमा वितरण किसी भी तरह से उसके एसोसिएट बैंक से जुड़ी नहीं हैं और सामान्य रूप से चालू रहेंगी।

, वित्तीय आवंटन में औसतन १० प्रतिशत का इजाफा गयामा गराबा खत्म करन पर प्रयास तज



अंतरिम बजट में सरकार ने उन सभी मदों के वित्तीय आवंटन में औसतन 10 प्रतिशत से अधिक की बढोतरी की है जो लोगों को बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में सहायक होते हैं।सरकार के प्रयास से पिछले नौ सालों में 24.82 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकाला गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लिए 80671 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है ।

नई दिल्ली।बहुआयामी गरीबी से देश की

सभी जनता को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए सरकार का प्रयास अंतरिम बजट में भी दिखा। अंतरिम बजट में सरकार ने उन सभी मदों के वित्तीय आवंटन में औसतन 10 प्रतिशत से अधिक की बढोतरी की है जो लोगों को बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकालने में सहायक होते हैं।

पोषण, बच्चों की मृत्यु दर, माताओं का स्वास्थ्य, स्कूल में बिताएँ जाने वाले साल, स्कूल में बच्चों की हाजिरी, खाना पकाने के ईंधन, स्वच्छता, बिजली, पेयजल, आवास, संपदा व बैंक खातों सुविधाओं के आधार पर बहुआयामी गरीबी को मापा जाता है। ये ऐसी सुविधाएं हैं जिसे मिलने से लोग खुद को गरीब नहीं समझते हैं। भले ही उनकी नकद आय नहीं बढी हो।

नौ सालों में 24.82 करोड़ दायरे से

नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के प्रयास से पिछले नौ सालों में 24.82 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर निकाला गया है। अब भी 15 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी के शिकार है।आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए गत

गुरुवार को पेश अंतरिम बजट में बहुआयामी गरीबी से जुड़े मानकों में सबसे अधिक 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी आवास के मद में की गई

प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लिए 80671 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जबकि चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के मुताबिक इस मद में 54103 करोड़ रुपए खर्च होंगे । प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के मद में आगामी वित्त वर्ष के लिए 12467 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जबकि चालू वित्त वर्ष में संशोधित

अनुमान के मुताबिक इस मद में 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

LPG कनेक्शन के लिए 9094 करोड़ रुपए खर्च

गरीब परिवारों के एलपीजी कनेक्शन के लिए आगामी वित्त वर्ष में 9094 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है जबकि चालू वित्त वर्ष में इस मद में 8500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। स्वच्छता के मद में आगामी वित्त वर्ष के लिए 7192 करोड़ का आवंटन किया गया है जबकि चालू वित्त वर्ष में इस मद में 7000 करोड़ खर्च होने का अनुमान है।

राजस्थान विधानसभा मारवाङ्

हैदराबाद का दौरा

जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी

ब्यूरो चीफ जगदीश सीरवी

हैदराबाद। जीडीमीटला कोमपल्ली राजस्थान से भाजपा विधायक केसराराम

चौधरी हैदराबाद शहर का दौरा करने के अवसर पर कुतबुल्लापुर पूर्व विधायक और

भाजपा नेता श्री कोना श्रीशैलम गौड ने कोमपल्ली में उनके कार्यालय में मलाकात की।

बैठक में आगामी संसदीय चनावों के साथ-साथ कई राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। इस

सम्मान किया। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता केकेएम ट्रस्ट अध्यक्ष श्री कोना श्रीनिवास

अवसर पर श्रीशैलम गौड़ ने राजस्थान भाजपा विधायक श्री केसराराम चौधरी का

गौड भाजपा नेता बालप्पा और सीरवी समाज बन्धुओं अन्य मौजूद हैं।

10वीं में 10 तो 12वीं में छह विषयों में पास होना जरूरी

www.newsparivahan.com

कला शिक्षा. शारीरिक शिक्षा और कल्याण,

विद्यार्थी को सभी 10 विषयों में उत्तीर्ण होना होगा।

12वीं में दो भाषा विषय होंगे शामिल

12वीं में अब विद्यार्थियों को एक के बजाय दो

भाषाएं पढ़नी होंगी। इसमें कम से कम एक भाषा भारत

में बोली जाने वाली होगी, वहीं चार मख्य विषय और

एक वैकल्पिक विषय होगा। यह सभी विद्यार्थियों को

चयनित करने होंगे। एनसीएफ के तहत इन विषयों को

पें टग, शारीरिक शिक्षा और कल्याण व व्यावसायिक

दूसरे समूह में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान,

अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र,

भौतिकी, रसायन विज्ञान व जीव विज्ञान शामिल है।

क्रेडिट के आवंटन के लिए कुल अनुमानित 1200

शिक्षण घंटे प्रति वर्ष होंगे, जिसके लिए 40 क्रेडिट दिए

गणित, प्रोग्रा "मग व कोडिंग, बिजनेस गणित,

वाणिज्य व पर्यावरण शिक्षा शामिल है। तीसरे समूह में

तीन समूह में बांटा गया है। जिसमें से विद्यार्थियों को

किसी दो समूह से चार विषय चयनित करने होंगे।

पहले समूह में संगीत, नृत्य, थिएटर, स्कल्पचर,

शैक्षणिक सत्र 2024-25 से देशभर में होंगे महत्वपूर्ण बदलाव

परिवहन विशेष न्यूज

शैक्षणिक सत्र 2024-25 से देशभर के शैक्षणिक ढांचे में महत्वपर्ण बदलाव किए जाएंगे। नए सत्र से नौवीं और 10वीं में विद्यार्थियों को 10 विषय पढ़ने होंगे और प्रत्येक में पास होना अनिवार्य होगा। एनसीआरएफ के तहत क्रेडिट गणना के लिए 30 शिक्षण घंटों को एक क्रेडिट के रूप में गिना जाएगा। विद्यार्थियों की एक सत्र में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति जरूरी।

नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा में गतिशीलता और आमूल चूल परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसके तहत विद्यार्थियों को शैक्षणिक विषयों और कौशल विषयों में क्रेडिट देना शामिल है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च-स्तरीय समिति ने स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा तक एक एकीकृत क्रेडिट संचय और हस्तांतरण ढांचा

10वीं में विद्यार्थियों को पढ़ने होंगे 10 विषय

इसके तहत सभी राज्य बोर्ड, सीबीएसई और एनआईओएस बोर्ड से संबंधित स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को लागु करने के लिए दिशानिर्देश (एसओपी) विकसित किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2024-25 से देशभर के शैक्षणिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। नए सत्र से नौवीं और 10वीं में विद्यार्थियों को 10 विषय पढ़ने होंगे और प्रत्येक में पास होना अनिवार्य होगा।

वहीं 12वीं में विद्यार्थियों को कुल छह विषय पढ़ने होंगे और प्रत्येक में पास होना अनिवार्य होगा। अब तक विद्यार्थी 10वीं में अधिकतम नौ विषय चन सकते थे, लेकिन वे छह विषय ही चुनते थे और पास होने के लिए पांच विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता था। वहीं 12वीं में कोई विद्यार्थी सात विषय चुन सकता था, जिसमें एक वैकल्पिक होता था। इसमें से विद्यार्थी को पांच विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता था।

10वीं में होंगी अब तीन भाषाएं

अब 10वीं कक्षा में तीन भाषाएं शामिल होंगी. जिसमें दो भाषा कम से कम भारत में बोली जाने वाली होगी, वहीं सात मुख्य विषय होंगे। इसमें गणित व



एनसीआरएफ के तहत क्रेडिट गणना के लिए 30 कम्प्युटेशनल थिंकिंग, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, शिक्षण घंटों को एक क्रेडिट के रूप में गिना जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा और अंतः विषय क्षेत्र शामिल हैं।

विद्यार्थियों की एक सत्र में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति जरूरी।

मख्य परीक्षाओं में क्रेडिट, विद्यार्थियों के ग्रेड कार्ड में अंकों और ग्रेड के साथ दर्शाया जाएगा।

अर्जित क्रेडिट विद्यार्थी के अकादिमक बैंक आफ क्रेडिट में जमा किया जाएगा जो छात्र के डिजिलाकर

प्रत्येक विषय सात क्रेडिट का होगा, एक सत्र में 210 घंटे आवंटित किए गए हैं।

प्रत्येक अध्याय के लिए घंटे आवंटित हैं और इसे आगे सैद्धांतिक और व्यावहारिक घंटों में विभाजित

क्रेडिट की गणना

एक क्रेडिट प्रति सप्ताह एक घंटे के शिक्षण या दो घंटे के व्यावहारिक कार्य क्षेत्र कार्य के बराबर होगा। एक क्रेडिट का मतलब 15 घंटे के सिद्धांत (थ्योरी) या 30 घंटे की कार्यशाला या प्रयोगशाला कार्य के

इलाहाबाद-राजस्थान समेत छह हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति, जानिए किसको कहां मिली जिम्मेदारी

इलाहाबाद और राजस्थान समेत छह हाई कोर्ट में शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई। इन सभी न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश गत दो नवंबर को सप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नियुक्तियों की घोषणा एक्स पोर्स्ट में की। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश अरुण भंसाली को इलाहाबाँद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

नर्ड दिल्ली। इलाहाबाद और राजस्थान समेत छह हाई कोर्ट में शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई। इन सभी न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश गत दो नवंबर को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नियुक्तियों की घोषणा एक्स पोस्ट में की।

राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश अरुण भंसाली को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी को उत्तराखंड हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह को ओडिशा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायाधीश बाहरी के उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद देश के 25 हाई कोर्ट में से दो का नेतृत्व महिलाएं करेंगी। जस्टिस सुनीता अग्रवाल गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं।

मेडचल घाटकेसर में चेरुकु बलाय्या सम्मेलन में केटी आर भाग लिया

मेडचल विधानसभा क्षेत्र में बीआरएस विजय केतनम फहराने के अवसर पर घाटकेसर मंडल पोचरम, घाटकेसर नगर पालिका, और बोडुपल, पिरजड़ी गुड़ा नगर पालिका के विजय पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री काल्वकुंतला तारकाराम राव (केटीआर) ने ओर बी आर एस पार्टी कार्यकर्ता ने घाटकेसर में चेरुकु बलाय्या सम्मेलन में भाग लिया



अब सरकारी भूमि से मिट्टी उठाने की अनुमति नहीं दे सकेगी पंचायतें

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

शाहपुरा। जिला कलक्टर टीकम चन्द बोहरा ने परिपत्र जारी कर बताया कि सरकारी बिलानाम अथवा चारागाह भूमि से मिट्टी दोहन हेतु कतिपय ग्राम पंचायतों द्वारा बिना किसी अधिकार के कतिपय व्यक्तियों या फर्मों को अनुमति अथवा अनापत्ति जारी कर दी जाती है

एवं इस हेत् राशि भी संबंधित ग्राम पंचायत में जमा करायी जाती है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम पंचायत का क्षेत्राधिकार आबादी भिम तक ही सीमित है, किसी भी राजकीय बिलानाम एवं चारागाह भूमि का स्वामित्व केवल राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार का ही है। इसलिए

ग्राम पंचायत द्वारा राजकीय भूमि से मिट्टी दोहन की दी गई अनुमति अनाधिकृत एवं अवैध है, ऐसी समस्त अनुमतियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त समझा जावे और यह सनिश्चितकिया जावे कि पूर्व में दी गई ऐसी अनुमतियों या अनापत्तियों के बदले प्राप्त राशि संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा तहसील कार्यालय में राजस्व मद

0029 में जमा कराई जाए। ने निर्देशित कर कहा कि समस्त पटवारियों, ग्राम विकास अधिकारियों एवं सरपंचो को इस आदेश की प्रति

जिला कलेक्टर टीकम चन्द बोहरा पालना हेतु प्रेषित की जाकर उनसे रसीद प्राप्त कर रेकार्ड पर रखी जाए। साथ ही भविष्य में यदि संबंधित ग्राम पंचायतों

द्वारा इस प्रकार की अनाधिकृत रूप से अवैध अनुमति या अनापत्ति राजकीय भूमि से मिट्टी दोहन के संबंध में जारी की जाती है, तो इस आदेश की अनुपालना में शिथिलता या उल्लंघन करने वाले संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक अथवा आपराधिक प्रकरण दर्ज किया

तेलंगाना इवेंट ऑर्गनाइजेशन का १५वां नर्सरी मेला आज से हैदराबाद में

ब्यूरो चीफ जगदीश सीरवी

तेलंगाना। इवेंट ऑर्गनाइजेशन द्वारा हैदराबाद के पीपल्स प्लाजा में 15वां भव्य नर्सरी मेला का आयोजन किया गया है। इस राष्ट्रीय स्तर के नर्सरी मेला का शुभारंभ 1 फरवरी को यानी आज प्रदेश के कृषि मंत्री थुम्मला नागेश्वर राव के हाथों पौधों और फूलों से सजे भव्य द्वार/पांडाल में हुआ। पांच दिनों तक चलने वाले इस नर्सरी मेला का समापन 5 फरवरी को होगा। मिली जानकारी के अनुसार, सुबह नौ बजे से रात नौ बजे तक चलने वाले में देशभर से 140 से ज्यादा व्यापारी अपने स्टॉल लगा रहे

पुणे, बेंगलुरु, तेलंगाना और आंध्र

प्रदेश सहित अन्य हिस्सों से आए व्यापारियों ने अपने स्टॉल यहां लगाए हैं जिसमें उपरोक्त के अलावा मुंबई, दिल्ली. समेत कई शहरों के नर्सरी प्रेमी भाग लेंगे।

इस नर्सरी मेला के निर्देशक खालिद अहमद जमीर ने नर्सरी टुडे को बताया कि इस मेले में 140 से अधिक स्टॉल पर अनेक प्रकार के फल-पौधे आगंतकों को आकर्षित कर रहे हैं। यहां ओरिएंटल लिली, हाइब्रिड डच ग्लैंडुलर, ऑर्किड, विभिन्न प्रकार के ट्यूलिप और गुलाब जैसे फूलों के पौधों की कई किस्मों का प्रदर्शन किया जा जा रहा

वहीं ग्रोमोर फ़ूड नर्सरी के

संचालक प्रवीण सत्यार्थी ने कहा कि इस नर्सरी मेला से दर्शकों को उम्मीद है कि यहां पौधों, फलों और सब्जियों के बीजों से लेकर पर्यावरण-अनुकुल बागवानी उत्पाद मेले में देखने को

नर्सरी मेला में मिलेंगे बोनसाई

नर्सरी मेला में जगह-जगह कई ट्रे ट्रीज़ / बोनसाई स्टुडियोज़ द्वारा स्थापित बोनसाई पौधे का स्टाल पौधे प्रेमियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। स्टॉल में अलग-अलग कीमत के विभिन्न बोनसाई पेड़ रहेंगे। इस मेले में घर की छत पर लगाने वाले बागवानी के पौधे भी रहेंगे। यहां गमले के अलावा पौधों में डालने वाले

उर्वरक भी मिलेंगे। इसके अलावा इस मेले में गमले, कोको बर्तन, बोन्साई लगाने के लिए बड़े गमले भी मिलेंगे।

गार्डन फर्नीचर भी मिलेंगे सत्यार्थी ने बताया कि नर्सरी मेला में रंग-बिरंगे फुलों-पौधों के अलावा लोग गार्डन फर्नीचर की भी खरीदारी कर सकते हैं। गार्डन फर्नीचर के अलावा सौंदर्य आकर्षण से गार्डन की शोभा बढाने वाली लाइट भी इस मेले में मिलेगी । गार्डन लाइट लोगों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। गार्डन लाइट से आप अपने घर के आसपास के गार्डन का डिजाइन कर सकते हैं। यह गार्डन की खूबसूरती में चारचांद लगाने का एक अच्छा ऑप्शन हैं।

ब्यूरो चीफ जगदीश सीरवी

तेलंगाना सरकार ने 8 फरवरी को छुट्टी की घोषणा की और है। तेलंगाना सरकार ने यह फैसला मुसलमानों के त्योहार शब-ए-मेराजके मौके पर लिया है। सरकार की ओर से जारी कैलेंडर में आठ फरवरी को शब- ए-मेराज का अवकाश घोषित किया गया है। लेकिन इसका उल्लेख वैकल्पिक अवकाश के अंतर्गत किया गया है।इसे सामान्य अवकाश के रूप में शामिल किया गया है।

यह अब नियमित अवकाश बन गया है। शब-ए-मेराज को मुसलमान एक शुभ दिन मानते हैं। उसे दिन मस्जिदों में को दीयों से सजाया सजाया जाता है। वे पुरी रात जागते हैं और प्रार्थना करते हैं। चुंकि 8 फरवरी को सामान्य अवकाश है, इसलिए सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी

तेलंगाना में ८ फरवरी को छुट्टी घोषित

गई है। लेकिन फरवरी में कोई नियमित छुट्टीयां नहीं हैं। आम त्योहार मार्च के बाद जनवरी में आते हैं। सरकार की ओर से जारी अवकाश कैलेंडर के मुताबिक 8 मार्च को माह शिवरात्रि के मौके पर छुट्टी है। 25 मार्च को होली का दिन है। 29 मार्च को गुड़ फ्राइडे के मौके पर छुट्टी दी गई थी। 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम जयंती के अवसर पर अवकाश घोषित किया

गया है। 9 अप्रैल को उगादी की छुट्टी है। 11और 12 अप्रैल को रमजान की छुट्टी घोषित की गई।14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती. 17 अप्रैल को श्री राम नवमी की छुट्टी भी दी गई है।

17 जुन को बकरीद की छुट्टी है। 17 जुलाई को मेहारम की छुट्टी, 29 जुलाई को बोनालो के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है 15



सितंबर को ईद नबी की छुट्टी दी गई थी।2 अक्टूबर को माहात्मा गांधी जयंती 12 और 13 अक्टूबर को दशहरा 31 अक्टूबर को दिवाली, नवंबर को गुरु नानक जयंती, 25 और 26 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी घोषित की गई।

लकपति दीदी कहाँ हैं? कोग्रेस नेता पचानन कानुनगी

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेस्वरः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2024-25 का मसौदा पेश किया. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। लेकिन कांग्रेस की शिकायत है कि आम लोगों को लाभ देने के लिए बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है । हालांकि इस बजट पर ओदिशा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पर्व वित्त मंत्री पंचानन कानूनगो ने प्रतिक्रिया दी है।लकपित दीदी



श्रीमती केस्त्रबाई सोनी की 34 वी पुण्यतिथि पर् संगम विश्वविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

भीलवाड़ा। स्थानीय संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा में श्रीमती केसरबाई सोनी की 34 वी पुण्यतिथि पर संगम विश्वविद्यालय की एनसीसी ,एनएसएस एवं सोशल क्लब के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया रक्तदान शिविर संयोजक) लेफ्टिनेंट राजकुमार जैन ने बताया कि रक्तदान शिविर का विधिवत उद्घाटन संगम इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अनुराग सोनी द्वारा किया गया। संगम विश्वविद्यालय के प्रो वीसी प्रोफेसर मानस रंजन



पाणिग्रही, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर राजीव मेहता,चीफ फाइनेंस अकाउंट ऑफिसर सतीश यादव,डेप्यूटी रजिस्ट्रार अनुराग शर्मा आदि के द्वारा सभी रक्त दाताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मान किया।विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो करुणेश सक्सेना ने सभी रक्तदाताओं तथा सफल आयोजन के लिए टीम सदस्यों को बधाई दी।लेफ्टीनेंट

राजकुमार जैन ने बताया की कुल 58 यूनिट का रक्तदान किया गया तथा जिसके सहयोग हेतु अरिहंत हॉस्पिटल के मेडिकल टीम सदस्य, एचआर सुरेंद्र सिंह, एनसीसी, एनएसएस आदि का धन्यवाद दिया गया।

मालदीव में अपने सैन्यकर्मी बदलेगा भारत, दोनों देशों के बीच बनी सहमति

मालदीव रिश्यत उड्डयन प्लेटफार्मों से भारत अपने सैन्यकर्मियों को बदलने को तैयार हो गया है। शुक्रवार को नई दिल्ली में भारत व मालदीव के बीच गठित उच्चरन्तरीय कोर समूह की बैठक में इस बारे में सहमति बनी है। मालदीव सरकार की तरफ से बताया गया है कि 10 मई 2024 तक मालदीव स्थित तीनों उड्डयन प्लेटफार्म से भारत अपने सैनिकों को बदल देगा।

नई दिल्ली।मालदीव स्थित उड्डयन प्लेटफार्मों से भारत अपने सैन्यकर्मियों को बदलने को तैयार हो गया है। शुक्रवार को नई दिल्ली में भारत व मालदीव के बीच गठित उच्चस्तरीय कोर समूह की बैठक में इस बारे में सहमति बनी है। मालदीव सरकार की तरफ से बताया गया है कि 10 मई, 2024 तक मालदीव स्थित तीनों उड्डयन प्लेटफार्म से भारत अपने सैनिकों को बदल देगा।

असैनिक कर्मचारियों व पदाधिकारियों से बदला जाएंगे कर्मी



माना जा रहा है कि भारत इन प्लेटफार्मों का संचालन असैनिक कर्मचारियों व पदाधिकारियों की मदद से करेगा। इसके लिए भारत सेना से सेवानिवृत्त कर्मियों की भी सेवा

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पिछले वर्ष वहां राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भारत की तरफ से निर्मित व संचालित इन उड्डयन प्लेटफार्मों से भारतीय सैन्यकर्मियों की वापसी को राजनीतिक मुद्दा बनाया था। इसके आधार पर ही उन्हें विजय हासिल हुई थी। राष्ट्रपति बनने के बाद भी मुइज्जू ने लगातार इसकी मांग की। मुइज्जू घोषित तौर पर चीन समर्थक नेता हैं।

विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

शुक्रवार को हुई उच्चस्तरीय कोर समूह की बैठक के बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गए हैं कि मालदीव की जनता की सेवा के लिए बनाए गए प्लेटफार्मों पर भारतीय सर्विस को जारी रखने के लिए दोनों पक्षों को स्वीकार्य समाधान निकाला जाएगा । यह समाधान क्या होगा, इस बारे में भारतीय पक्ष ने कुछ नहीं कहा है। इसकी जानकारी मालदीव के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी सूचना से मिली है।

भारत सरकार ने जताई सहमति इसके मृताबिक, भारत सरकार इस बात के लिए तैयार हो गई है कि वह अपने तीनों उड्डयन

प्लेटफार्म में से एक प्लेटफार्म से अपने

सैन्यकर्मियों को 10 मार्च, 2024 तक बदल

भारतीय सैन्यकर्मी काम करते हैं। यहां से दो हेलीकाप्टर और एक डोर्नियर विमान का संचालन होता है। मामले से जुड़े लोगों ने बताया है कि भारत कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। एक विकल्प यह है कि अनुभवी सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की नियुक्ति वहां की जाए। एक

देगी। 10 मई. 2024 तक सभी सैन्यकर्मियों

को बदल दिया जाएगा।भारत की तरफ से

निर्मित इन प्लेटफार्मों पर तकरीबन 75

विकल्प यह भी है कि इस पेशे में प्रशिक्षित सामान्य भारतीय नागरिकों की नियुक्ति वहां की जाए। कोर समूह की अगली बैठक माले में होगी, जिसमें अंतिम फैसला होने की संभावना है। कोर समूह की पहली बैठक 14 जनवरी को हुई थी।

मुइज्जू का रवैया पूरी तरह से भारत

सनद रहे कि गुरुवार को भारत सरकार की तरफ से पेश अंतरिम बजट में मालदीव के लिए आर्थिक मदद बढ़ाने का प्रविधान है। उधर, राष्ट्रपति बनने के बाद से ही मुइज्जू का रवैया पूरी तरह से भारत विरोधी है। चीन की यात्रा करने के बाद उनकी सरकार ने चीन के एक टोही जहाज को मालदीव के समुद्री तट का दौरा करने की भी अनुमति दी है। भारत इसको लेकर सतर्क है। वैसे मुइज्जू की इन नीतियों का घरेलू स्तर पर भी काफी विरोध हो रहा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-१८,१०२० सेक्टर ५९, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं ३, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-४, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- ११००६३ से प्रकाशित। सम्पर्क: 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी .आर .बी . एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। Title Code: DELHIN28985. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023